कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल
(शाखा-भू-प्रबंध)
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0 - 462003

क्रमांक/ F-1/831/2021/10-11/ भोपाल, दिनांक 29.10.2025

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली -110003

विषय:- बालाघाट जिले के परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष क्रमांक पीएफ-807 एवं पीएफ-809 के रकबा 28.02 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैगनीज ओर खनिज उत्खनन हेतु मेसर्स अर्पण फेरो एलाएस, बालाघाट को उपयोग पर देने बावत। ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भ:- भारत सरकार, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 6-MPF004/2022-BHO (E- 175974) दिनांक 29-09-2025

--0--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र0	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
i	It has been submitted by the State Government that the Mining plan of the instant proposal has been revoked by the IBM on 09.06.2021 and the matter for validity of the Mining Plan is under consideration with the Honorable High Court which implies that the matter is sub judice with regard to the validity of the mining plan. It is pertinent to mention here that as per Para 7.2 of Chapter-7 given under the Consolidated Handbook of Rules & Guidelines issued by the Ministry on dated 29.12.2023, the User Agency should have valid Mining Plan. Therefore, there is no justification for considering a mining proposal which does not have a valid and approved Mining plan as on date.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी दी है कि :- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 16.11.1993 को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसके तहत हमारा स्वीकृत माइनिंग प्लान वर्ष 1994 का दिनॉक 09.05.1994 को स्वीकृत है, इसी माइनिंग प्लान के आधार पर हमारी Forest Clearance की कार्यवाही चालु है। इसी माइनिंग प्लान Environment Clearance की कार्यवाही चल रही है, जिसके अंतर्गत हमें ToR की शर्ते प्राप्त हो चुकी है, (सलग्न) एवं ToR की शर्तो के आधार पर वन प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर ली गई है, (सलग्न) योजना शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, उपरोक्त माइनिंग प्लान पर EC के अंतर्गत जनसुनवाई हो चुकी है।(सलग्न) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार हमारा अनुबंध दिनॉक 11.01.2017 को हो चुका है एवं हमारे साथ अन्य के भी अनुबंध निर्धारित तिथी (11.01.2017) को हुए जिसमें से A P TRIVEDI SONS का अनुबंध हुआ, जिसमें रजिस्ट्रेशन कि तारिक 12.01.2017 आयी एवं Forest Clearance व Environment Clearance की कार्यवाही कर आज दिनॉक को उक्त खदान चालु है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (WP-378-2017) दिनाक 09.01.2017 में स्पष्ट करते हुए कहा है कि अर्ध न्यायिक कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही याचिकाकर्ता के पक्ष में तय होती है, तो कट-ऑफ तिथि पर सांविधिक समय सीमा (statutory limitation) याचिकाकर्ता को केंदीय सरकार द्वारा दी गई अनुमति का लाभ लेने में बाधा (not come in the way) बने। आवेदक संस्थान को अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना होगा।

ii	It has been submitted by the State Govt. that UA agreed to comply with all the conditions/provisions of section 10 A 2 (c) of MMDR Amendment Act, 2015. However, the Comments/ recommendation by the Mineral Resources Department, Govt. of Madhya Pradesh whether the lease/LoI is valid as on date in light of provisions of section 10 A (2)(c) of the MMDR Amendment Act, 2015 has not been submitted. The same needs submission	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा LOI/मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट म0प्र0 द्वारा अनुबंध वैद्य होने संबंधी पत्र की प्रति संलग्न की है।
iii	As per DSS examination, the area for safety zone is 1.72 Ha. whereas, as per the component wise breakup submitted in part-1 of the application form, the area for plantation is 1 ha. This needs clarification.	इस बिन्दु की पूर्ति आवेदक संस्था द्वारा की जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधित और सही किया गया है।
iv	As per the DSS examination, it is observed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the approach access Road (width varying from 0.65 m to 1.99 m) because the proposed Road is not found connected with any existing Road. The State Govt. is requested to submit the correct KML file as per the component wise breakup of the proposal.	इस बिन्दु की पूर्ति आवेदक संस्था द्वारा की जाकर KML को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
v	As per DSS Analysis, two earthen dam/ tanks are located at a distance of 378 meters and 336 meters respectively from the proposed forest land for mining. Thus, it cannot be stated whether the proposed forest land is part of the catchment area of these earthen dams/ tanks or otherwise. This needs to be clarified by the State Government.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा दो मिट्टी के बांधो/ टैंकों की सुरक्षा हेतु खदान क्षेत्र का भू-जलविज्ञान अध्ययन और आसपास के जलाशयों की संरक्षण योजना तैयार कर संलग्न की गई है। इसे परिवेश पौर्टल पर ऑनलाइन अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में भी अपलोड किया गया है।
vi	The State Govt. reported that 17.0565 ha Non-Forest area for CA has been proposed in village Dhipur whereas the KML file has been uploaded for an area of 15.83 ha. Similarly, KML file area of CA land in Village Khapakheda has been found to be 12.38 ha instead of 10.9635 ha actually proposed as per the proposal. The correct KML files of the Non-forest land proposed for CA needs to be uploaded online on PARIVESH portal.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित KML फाईल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान से प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 29-10-2025
13:29:56

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
3 मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट, मध्यप्रदेश-481001

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

ARPAN FERRO ALLOYS

MANUFACTUR OF FERRO MANGANESE

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001

Email id:arpanferroalloys531@gmail.com **Ph. No.:** 9425138765, 9399719481

प्रति, दिनॉक–27/10/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू–प्रबंध)

मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषयः–वन मंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष कमांक PF-807 & PF-809 के रकबा 28.02 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पध्दति से मैंगनीज ओर खनिज उत्तखनन का मेंसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी बालाघाट, प्रकरण कमांक FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भः–(1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक 6-MPR004/2022-BHO/(E-175974 दिनॉक 29/09/2025

(2) आपके कार्यालय के पत्र कमांक /एफ–1/831/2021/10-11-2477 दिनॉक 01/10/2025.

महोदय

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र कमांक 6-MPR004/2022-BHO/(E-175974 दिनॉक 29/09/2025 से प्रकरण मे 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी है। जिसमे से चाही गयी जानकारी का जवाब टेबुलर फार्म मे अवलोकनार्थ सम्प्रेषित हैः–

क्र	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	It has been submitted by the State Government that the Mining plan of the instant proposal has been revoked by the IBM on 09.06.2021 and the matter for validity of the Mining Plan is under consideration with the Honorable High Court which implies that the matter is sub judice with regard to the validity of the mining plan. It is pertinent to mention here that as per Para 7.2 of Chapter-7 given under the Consolidated Handbook of Rules & Guidelines issued by the Ministry on dated 29.12.2023, the User Agency should have valid Mining Plan.	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 16.11.1993 को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसके तहत हमारा स्वीकृत माइनिंग प्लान वर्ष 1994 का दिनॉक 09.05.1994 को स्वीकृत है, इसी माइनिंग प्लान के आधार पर हमारी Forest Clearance की कार्यवाही चालु है। इसी माइनिंग प्लान Environment Clearance की कार्यवाही चल रही है, जिसके अंतर्गत हमें ToR की शर्ते प्राप्त हो चुकी है, (सलग्न) एवं ToR की शर्तो के आधार पर वन प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर ली गई है, (सलग्न) योजना शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, उपरोक्त माइनिंग प्लान पर EC के अंतर्गत

	Therefore, there is no justification for considering a mining proposal which does not have a valid and approved Mining plan as on date.	जनसुनवाई हो चुकी है।(सलग्न) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार हमारा अनुबंध दिनॉक 11.01.2017 को हो चुका है एवं हमारे साथ अन्य के भी अनुबंध निर्धारित तिथी (11.01.2017) को हुए जिसमें से A P TRIVEDI SONS का अनुबंध हुआ, जिसमें रजिस्ट्रेशन कि तारिक 12.01.2017 आयी एवं Forest Clearance व Environment Clearance की कार्यवाही कर आज दिनॉक को उक्त खदान चालु है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (WP-378-2017) दिनाक 09.01.2017 में स्पष्ट करते हुए कहा है कि अर्ध न्यायिक कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही याचिकाकर्ता के पक्ष में तय होती है, तो कट–ऑफ तिथि पर सांविधिक समय सीमा (statutory limitation) याचिकाकर्ता को केंदीय सरकार द्वारा दी गई अनुमति का लाभ लेने में बाधा (not come in the way)न बने।
2	It has been submitted by the State Govt. that UA agreed to comply with all the conditions/provisions of section 10 A 2 (c) of MMDR Amendment Act, 2015. However, the Comments/ recommendation by the Mineral Resources Department, Govt. of Madhya Pradesh whether the lease/Lol is valid as on date in light of provisions of section 10 A (2)(c) of the MMDR Amendment Act, 2015 has not been submitted.The same needs submission	मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार हमारा अनुबंध दिनॉक 11.01.2017 को 50 वर्ष के लिए (10.01.2067 तक) स्वीकृत किया गया है। –कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट म0प्र0 द्वारा अनुबंध वैद्य होने का पत्र दिया गया है।(सलग्न) –संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल म0प्र0 के पत्रानुसार पट्टा (अनुबंध) वैद्य है।(सलग्न)
3	As per DSS examination, the area for safety zone is 1.72 Ha. whereas,	वृक्षारोपन के लिए क्षेत्र को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन संशोधित और सही किया

	as per the component wise breakup submitted in part-1 of the application form, the area for plantation is 1 ha. This needs clarification.	गया है।
4	As per the DSS examination, it is observed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the approach access Road (width varying from 0.65 m to 1.99 m) because the proposed Road is not found connected with any existing Road. The State Govt. is requested to submit the correct KML file as per the component wise breakup of the proposal.	KML को सुधारा गया है और उसे परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है।
5	As per DSS Analysis, two earthen dam/ tanks are located at a distance of 378 meters and 336 meters respectively from the proposed forest land for mining. Thus, it cannot be stated whether the proposed forest land is part of the catchment area of these earthen dams/ tanks or otherwise. This needs to be clarified by the State Government.	दो मिट्टी के बांधो/ टैंकों की सुरक्षा हेतु खदान क्षेत्र का भू–जलविज्ञान अध्ययन और आसपास के जलाशयों की संरक्षण योजना तैयार कर संलग्न की गई है। इसे परिवेश पौर्टल पर ऑनलाइन अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में भी अपलोड किया गया है।
6	The State Govt. reported that 17.0565 ha Non-Forest area for CA has been proposed in village Dhipur whereas the KML file has been uploaded for an area of 15.83 ha. Similarly, KML file area of CA land in Village Khapakheda has been found to be 12.38 ha instead of 10.9635 ha actually proposed as per the proposal. The correct KML files of the Non-forest land proposed for CA needs to be uploaded online on PARIVESH portal.	दोनो भूमियों के लिए KML में सुधार किया गया है। CA भूमि के लिए प्रस्तावित गैर–वन भूमि की सही KML फाइल परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है।

ARPAN FERRO ALLOYS

MANUFACTUR OF FERRO MANGANESE

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001

Email id:arpanferroalloys531@gmail.com **Ph. No.:** 9425138765, 9399719481

सलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(जानकारी 02 प्रतियो में)

भवदीय

अर्पण फेरो एलायस

प्रतिलिपिः–

1. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, दक्षिण बालाघाट, म0प्र0।

भवदीय

अर्पण फेरो एलायस

ANNEXURE - D.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
.. ..

No. 5/25/93-M.IV New Delhi, the 16th November, 1993.

To

The Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh,
Department of Mineral Resources,
BHOPAL-462003.

Subject:- Grant/~~Renewal~~ of ML/~~PL~~ for Manganese over an area of 69.22 acres in Village Mohgaonghat, District Balaghat in favour of M/s. Arpan Ferro Alloys

.. ..

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.2-99/93/12/2 dated 17.5.93 on the above mentioned subject and to convey the approval of the Central Government under Section 5(1) of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 to the grant of mining lease/~~prospecting licence~~ for Manganese over an area of 69.22 acres in Village Mohgaonghat, District Balaghat in favour of M/s. Arpan Ferro Alloys for a period of 20 (twenty) years.

2. Before allowing grant ~~of ML/PL/Renewal~~ of mining lease, the State Govt. may kindly ensure the compliance of the amended provisions of the Act and Rules, and other applicable Acts and Rules including Forest (Conservation) Act, 1980.

3. A copy of the orders passed by the State Govt. in the matter may kindly be furnished to this Ministry for record.

Yours faithfully,

(K.S. BAJWA)
DIRECTOR

Registered

Copy to :-

1. The Controller General, Indian Bureau of Mines, Indira Bhawan, Civil Lines, NAGPUR-440 001.
2. The Ministry of Steel (RMI Section), Udyog Bhawan, New Delhi, w.r.t. their O.M. No. 15(16)/93-RMI dated 6.7.93
3. PS to MOS(Mines)
4. Guard File.

Sd/-

(K.S. BAJWA)
DIRECTOR

Annexure 1.2

C. P. AMBESH
REGIONAL CONTROLLER OF MINES

तार : खान ब्यूरो
Telegram : MINESBURO
टेलेक्स/Telex : 0715-307 IBM IN
दूरभाष/Telephones :
कार्यालय / Office : 525089
निवास / Res. : 520798

क्र. BGT/MN/MPLN - 357 / NGP
No.

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
इंदिरा भवन, आय. बी. एम. मुख्यालय
सिव्हिल लाईन्स,

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Mines
INDIAN BUREAU OF MINES
Indira Bhavan, IBM Headquarters,
Civil Lines,

नागपुर-440001, दिनांक 9 / 5 / 1994
NAGPUR-440001, the

To,

M/s Arpan Ferro Alloys
Prop: Smt. Hemlata Chaturmohta,
Kosmi, Gondia Road,
Balaghat (M.P.) - 481001

Subject : Approval of 'Mining Plan' in respect of your Mohagaonghat Manganese Deposit over an area of 28.02 Hect. in district Balaghat State Madhya Pradesh, for grant of Mining Lease.

Reference: i) Your consultant's letter No. SVG/IBM/L/94 dated 5.5.94 submitting therewith the modified 'Mining Plan'.
ii) Our letter of even no. dated 29.4.94.

Dear Sir,

In exercise of the powers conferred in me by Clause (b) of Sub Section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 read with Govt. of India Order No. S.O.445 (E) dated 26.4.87, I hereby APPROVE the above said 'mining plan'. This approval is subject to the following conditions.

1) This 'Mining Plan' is approved without prejudice to any other laws applicable to the mine/area from time to time whether made by Central Government, State Govt. or any other authority.

2) The approval of your aforesaid 'Mining Plan' does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provisions of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 or the rules framed there-under, and any other laws.

Encl.: Approved 'Mining Plan' four copies.

Yours faithfully,
9/5/94
(C.P. Ambesh)
Regional Controller of Mines
Indian Bureau of Mines. (NR)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859

No: 2807 / SEIAA/2024
Date: 12/2/24

प्रति,

मेसर्स अर्पण फेरो एलायज, प्रोपराईटर,
श्री अनिल चतुरमोहता आत्मज इंदरचंद चतुरमोहता,
निवासी वार्ड नं0 11, एफसीआई कोसमी के सामने, बालाघाट,
जिला–बालाघाट (म0प्र0)

विषयः– **प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/418774/2023 प्रकरण क्र. 10080 / 2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अर्पण फेरो एलायज, प्रोपराईटर, श्री अनिल चतुरमोहता आत्मज इंदरचंद चतुरमोहता, निवासी वार्ड नं0 11, एफसीआई कोसमी के सामने, बालाघाट, जिला–बालाघाट (म0प्र0) द्वारा मैंगजीन ओर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5741.77 घन प्रतिवर्ष, रकबा 28.01 हे0 खसरा क्रमांक 396, ग्राम– मोहगांवघाट, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। **Prescribing of TOR**

संदर्भः– SEIAA की बैठक 809वी एवं 826वी दिनांक 04.10.2023 एवं दिनांक 23.01.2024 एवं SEAC समिति की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 एंव, 704 वी बैठक दिनांक 19.12.2023 ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 704वी बैठक दिनांक 19.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

I. SEIAA द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त शर्तें :–

".....राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 एवं 704 वी बैठक दिनांक 19.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

(x) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(xi) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(xii) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xiv) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर

उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

(xvii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

(xviii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।....."

II. SEAC द्वारा अनुशंसित विशिष्ट शर्तें :–

".....उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:–

(xix) ईआईए रिपोर्ट के साथ स्टेज–1 फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

(xx) प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xxi) प्रश्नाधीन खदान के उत्तर पूर्व दिशा – जल निकाय क्षेत्र 336 मीटर तथा पूर्व दिशा– जल निकाय क्षेत्र 327 मीटर पर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xxii) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxiii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xxiv) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxv) भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxvi) परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

(xxvii) क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाईल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये।

(xxviii) खदान क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत है, अतः वाईल्ड लाईफ संरक्षण योजना के साथ फॉरेस्ट क्लीयरेंस संबंधी दस्तावेज ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये । ....."

III. SEAC द्वारा परिशिष्ट–डी अनुसार अनुशंसित मानक शर्तें :–

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analysed.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages

are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.

29. LPG gas shall be provided for camping labour under "UjjwalaYojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. **Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:**
    - Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "UjjwalaYojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. **Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :**
    - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned/Gram Panchayat/ Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

Validity:–

- The TORs prescribed for the project will be valid for a period of four years for submission of EIA and EMP report accordingly, the TORs will lapse after 22.01.2028.
- This period of validity could be extended by the Regulatory Authority concerned by a maximum period of one year provided an application is made by the applicant to the Regulatory Authority before the expiry of validity period, together with updated Form-I based on proper justification and also recommendation SEIAA/SEAC.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

Endt No. 280 / SEIAA/24 Dated: 12/2/24

Copy to:-

1. सदस्य सचिव, SEAC, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूतल सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, व शंकर नगर, भोपाल – 462016।
5. डाटा एन्ट्रीआपरेटर, की ओर परिवेश पोर्टल एवं MP-SEIAA की वेब–साईट पर अपलोड करने बावत्।
6. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Annexure 1.4

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003
दूरभाष : 0755-2674249, 2554275, फैक्स : 0755-2674208 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/व.प्रा./कक्ष-1/MINE-205/3232   भोपाल, दिनांक 18-10-2024

प्रति,

श्री अनिल भतुरमोहता,
मेसर्स अर्पण फेरो एलायंस बालाघाट,
गोंदिया रोड, कोसमी बालाघाट-481001

विषय :- मेसर्स अर्पण फेरो एलायंस बालाघाट का दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के परिक्षेत्र लौरलांजी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 807 एवं 809 में रकबा 28.02 हे. वनभूमि में मैगनीज और खनन हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MINE/19894/2016 में वन्यजीव संरक्षण योजना।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 15.05.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट का पत्र क्रमांक/तक.शाखा/1371 दिनांक 26.09.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से आपके द्वारा मेसर्स अर्पण फेरो एलायंस बालाघाट के दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के परिक्षेत्र लौरलांजी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 807 एवं 809 में रकबा 28.02 हेक्टेयर वनभूमि में मैगनीज और खनन हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MINE/19894/2016 के संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/2807/SEIAA/2024 दिनांक 12.02.2024 से सशर्त स्वीकृति प्रदाय की गई है। इस स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-II की शर्त (xxviii) तथा शर्त III मानक शर्त क्रमांक 27 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित मैगनीज माइन के आस-पास फ्लोरा-फौना पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु क्षेत्र में पाये जाने वाले फ्लोरा-फौना की सूची संलग्न कर तथा 10 वर्षों के लिए रूपये 34.00 लाख की वन्यजीव संरक्षण योजना मेसर्स ACHYUT ENVIRO CONSULTANT, Nagpur से तैयार कराकर इस कार्यालय के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। उक्त वन्यजीव संरक्षण योजना का वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के पत्र क्रमांक/तकनीकी/1183 दिनांक 17.09.2024 से सूक्ष्म परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त को प्रेषित की गई। जिसे मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 26.09.2024 से रूपये 41.616 की 05 वर्षों की वन्यजीव संरक्षण योजना अनुशंसा सहित इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। प्रस्तावित संशोधित वन्यजीव संरक्षण योजना Miscellaneous Administration and Monitoring expenses (@2% of the total costs तथा Escalation cost and unforeseen expenditure @20% of total costs का प्रावधान कर 05 वर्षों के लिए रूपये 41.616 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रकरण मे वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त द्वारा उक्त वन्यजीव संरक्षण योजना में 05 वर्षों के लिए प्राक्कलित कार्यों एवं रूपये 41.616 लाख राशि की अनुशंसा की गई है, जिसके मुख्य घटक एवं प्राक्कलित राशि निम्नानुसार है–

Sr. No.	Particulars	Year wise Financial Projections (Rs. in Lacs)					
		I	II	III	IV	V	Total
1.	**Habitat improvement & mitigative measures**						
a)	Habitat Improvement by development of vegetation cover by plantation with suitable species	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	6.00
b)	Biological fence (Bamboo species, Euphorbia sp., Agave americana, etc.) around the habitation and around the agriculture fields adjoining to forest area to control human wildlife conflict	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	4.00
c)	Prevention of Forest Fire: Training and Infrastructure facilities	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.00
d)	Construction and filling of water holes and ponds in wildlife habitat	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
2.	**Awareness and Extension**						
a)	Training and capacity building for volunteers and officials of forest department	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.40
3.	**Support to Forest Department for monitoring, rescue & rehabilitation of wildlife**						
a)	Support/Provision of veterinary care, cages, recuse centers, etc.	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.40
4.	**Contribution towards conservation of wildlife in PAS**						
a)	Contribution towards conservation of wildlife in PAS	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.40
5.	**Administrative Cost for processing inspections etc. (To be deposited in RPACS)**						
	Administrative Cost for processing inspections etc	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.40
6.	**Miscellaneous including Eco- development**						
a)	Miscellaneous including Eco- development	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	3.40
	Total	**6.8**	**6.8**	**6.8**	**6.8**	**6.8**	**34.00**
b)	**Miscellaneous Administrative & Monitoring Expenses**						
	Miscellaneous Administrative & Monitoring Expenses (2% of project cost)	0.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.68
c)	**Escalation Cost & Unforeseen**						
	Escalation Cost & Unforeseen (20% of project cost)	6.936	0.0	0.0	0.0	0.0	6.936
	Grand Total	**14.416**	**6.80**	**6.80**	**6.80**	**6.80**	**41.616**

वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट द्वारा अनुशंसित वन्यजीव संरक्षण योजना के पृष्ठ क्रमांक 36 से 45 में उल्लेखित फ्लोरा–फौना की सूची एवं उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन्यजीवों के संरक्षण प्रबंधन हेतु पृष्ठ क्रमांक 71 से 73 पर दर्शाये गये कार्यों के लिए रुपये 41.616 लाख की 05 वर्षों की वन्यजीव संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त एवं एक प्रति वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट को उपलब्ध करावें।

प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत समय-सीमा में वन्यजीव प्रबंधन योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले प्राक्कलित कार्यों हेतु योजना में प्राक्कलित राशि रुपये 41.616 लाख (रुपये इकतालीस लाख छह सौ सोलह मात्र) एक मुश्त कैम्पा मद में जमा कराये जाकर वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आपके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करावेंगे।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

(वी.एन. अम्बाडे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 18-10-2024

पृ.क्रमांक/म.प्र./काज.-1/MINE-205/3233

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, SEIAA Madhya Pradesh पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल -462016 की ओर उनके पत्र दिनांक 12.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति में अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना में प्राक्कलित राशि रुपये 41.616 लाख आवेदक संस्था द्वारा वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट को एक मुश्त उपलब्ध कराने एवं कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने की शर्त अधिरोपित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट की ओर उक्त अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति के उपरांत माइन प्रारंभ होने के पूर्व वन्यजीव संरक्षण योजना में वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए प्राक्कलित राशि एक मुश्त राशि आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्राक्कलित कार्यों का समय सीमा में क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PARYAWARAN PARISAR E-5, ARERA COLONY BHOPAL-462016
Tel: 0755-2464428,2466191 Fax: 0755-2463742

No. /TS /Mine/MPPCB/2024 Bhopal dt.

To,

Regional Officer,
Regional Office,
M.P. Pollution Control Board,
Jabalpur (M. P.)

Sub: Order to Conduct Public Hearing under EIA Notification No. 1533 dtd. 14/09/06 regarding Environmental Clearance of **M/s Arpan Ferro Alloys , Manganese Ore Mine** Kh No. 396 at Village: Mohagaonghat Tehsil: Waraseoni Distt: Balaghat (M.P.) **Area: 28.02 hect.**

Ref: 1. Mine letter No: Nil Date:21.03.2024, received on date 12.04.2024.
2. TOR issued SEIAA vide Lett. No:2807 dated:12.02.2024,**Case No 10080/2023**

M/s Arpan Ferro Alloys , Manganese Ore Mine Kh No. 396 at Village: Mohagaonghat Tehsil: Waraseoni Distt: Balaghat (M.P.) Area: 28.02 hect. has submitted an application for Public hearing as per the provisions of EIA Notification No. 1533 date. 14/09/06 with draft EIA report for **Manganese Ore Mine, Production Capacity: Manganese Ore Mine: 5,741.77 Cum/Annum ,**

1. Letter of request.
2. Hard Copy of the draft EIA report.
3. Soft copy of the draft EIA report.
4. Executive Summary of the draft EIA report in English & Hindi (Hard Copy)
5. Executive Summary of the draft EIA report in English & Hindi (Soft Copy)
6. Copy of TOR

Now, you are hereby, directed to finalize, the date, time & exact venue for the Public hearing as per the provisions of the notification, in consultation with the district Collector. The same shall be advertise in one major National daily & One regional vernacular daily. A minimum notice period of 30 days as per the provisions of the notification shall be provided to the public for furnishing their respo nses. The information about the places or offices where the Public could access the draft rapid EIA report & the summary of REIA report before the due date of public hearing shall also be mentioned in the advertisement. You are also directed to adhere to the procedure for conduct of Public Hearing as prescribed in the notification. **The office memorandum no. J-11015/387/2008-IA.11 (m) dated 28/09/ 2011** is enclosed herewith for the reference in this regard.

ENCL: As above.

for **(A.A.Mishra)**
Member Secretary

Scanned with OKEN Scanner

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PARYAWARAN PARISAR E-5, ARERA COLONY BHOPAL-462016
Tel: 0755-2464428,2466191 Fax: 0755-2463742

Endt. No. 2100 /TS /Mine/MPPCB/2024 Bhopal dt. 16-4-2024
Copy to:

1. **Collector, Distt: Balaghat** for Information and finalizing the date of Public hearing at the earliest for the project as per the provisions of the EIA Notification 2006,

2. **M/s Arpan Ferro Alloys ,** Shri Anil Chaturmohta Address: Ward - 11 FCI Infront of Kosmi **Distt: Balaghat (M.P.)** for information. You are requested to contact the Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, **Jabalpur** (M.P.) regarding conduction of public hearing. It is also requested to forward, one Hard & One Soft copy of the above draft EIA report along with the summary of EIA report, to the following authorities or offices within whose jurisdiction the project is being located at the earliest.
   a Distt. Magistrate.
   b Zila Parisad or Municipal Corporation.
   c. Distt. Industries Office.
   d. Regional Office of the MOEF, Bhopal.
3. Shri Arvind Pare public hearing work Technical Section, M.P. Pollution Control Board, Bhopal. One Soft Copy of the draft EIA report & Executive Summary of the project in English & Hindi is enclosed for uploading the same on the official web site of the Board for display as per the provisions of the notification.

for **(A.A.Mishra)**
Member Secretary

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 1.6

क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

कमांक––1401––––/क्षे.का/प्रनिबो/2024 जबलपुर,दिनांक–30/09/24

प्रति,

मेसर्स अर्पण फेरों अलॉयस,
श्री अनिल चतुरमोहता,
वार्ड–11 एफसीआई के सामने कोसमी,
जिला बालाघाट (म0प्र0)

विषय–दैनिक समाचार पत्रों में लोक सुनवाई की आम सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेसर्स अर्पण फेरों अलॉयस, मैगनीज ओर माईन कंपार्टमेंट नं. 807 एवं 809 (पूर्व खसरा नं0 396) ग्राम मोहंगॉवघाट, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट, रकवा 28.02 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता मैगनीज ओर माईन–5,741.77 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सुनवाई की आम सूचना एक राष्ट्रीय स्तर एवं एक स्थानीय प्रकाशित समाचार पत्रों के सर्वत्र प्रकाशित पृष्ठ पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्रों की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये आम सूचना से संबंधित बिलों का सीधे अपने स्तर से भुगतान करने का कष्ट करें।

कृपया यह सुनिश्चित किया जावे कि समाचार पत्रों में आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 05.10.2024 के पूर्व आवश्यक रूप से हो जावे ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी
जबलपुर

पृ0क0...../क्षे.का./प्र.नि.बो./2024 जबलपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि–

1–कलेक्टर, बालाघाट की ओर पत्र कमांक 921/खनिज/2024, दिनांक 30.09.2024 के संबंध में सूचनार्थ।
2–प्रभारी, आई.टी. शाखा, म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वेवसाइट पर जानकारी देने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

कमांक————————/क्षे.का/प्रनिबो/2024 जबलपुर,दिनांक————————

प्रति,

1– कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय, जिला बालाघाट

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट

3– सचिव, ग्राम पंचायत ग्राम मोहंगॉवघाट, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट

विषय– मेसर्स अर्पण फेरों अलॉयस, मैगनीज ओर माईन कंपार्टमेंट नं. 807 एवं 809 (पूर्व खसरा नं0 396) ग्राम मोहंगॉवघाट, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट, रकवा 28.02 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता मैगनीज ओर माईन–5,741.77 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 06.11.2024 का कार्यवाही विवरण जन सामान्य के अवलोकनार्थ रखे जाने बावद।

ई.आई.ऐ. नोटिफिकेशन कमांक एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स अर्पण फेरों अलॉयस, मैगनीज ओर माईन कंपार्टमेंट नं. 807 एवं 809 (पूर्व खसरा नं0 396) ग्राम मोहंगॉवघाट, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट, रकवा 28.02 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता मैगनीज ओर माईन–5,741.77 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुकम में दिनांक 06.11.2024 को लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। उक्त अधिसूचना के प्रावधान अनुसार कार्यवाही विवरण की एक प्रति जन सामान्य के अवलोकनार्थ आपके कार्यालय में रखी जाना है। अतः कार्यवाही विवरण की प्रति आपकी ओर जन सामान्य के अवलोकनार्थ रखे जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नकः– कार्यवाही विवरण।

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी

कमांक 1844/क्षे.का./प्र.नि.बो./2024 जबलपुर दिनांक 16/12/24

प्रतिलिपिः–

1. मेसर्स अर्पण फेरों अलॉयस, श्री अनिल चतुरमोहता, वार्ड–11 एफसीआई के सामने कोसमी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक

क्रमांक एफ 2-99/1993/12/2:- मेसर्स अर्पण फैरो अलायस के पक्ष में जिला बालाघाट के ग्राम मोहगांवघाट के खसरा क्र. 396 के रकबा 69.22 एकड़ क्षेत्र पर मैगनीज खनिज का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र कमांक 5/25/1993/एम-चार दिनांक 16.11.1993 से धारा 5(1) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके पालन में राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 24.05.1994 से खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था। आवेदक द्वारा अनुबंध निष्पादन की समस्त औपचारिकताए पूर्ण कर दी गई थी। परंतु अनुबंध निष्पादन नहीं हो सका। इसका कारण यह था कि राज्य शासन द्वारा यह निर्णय राजस्व भूमि प्रतिवेदित होने के आधार पर लिया गया था। परंतु यह क्षेत्र वन कक्ष क्र. 807 का भाग होने के कारण अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संबंधित क्षेत्र के संबंध में राजस्व भूमि मान्य करते हुये दिनांक 16.11.1993 से धारा 5(1) के तहत दिये गये अनुमोदन को वन क्षेत्र मान्य करते हुये पुनरीक्षित अनुमोदन दिये जाने हेतु पत्र दिनांक 15.01.2014 से लेख किया गया। आज दिनांक तक भारत सरकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका है। इसी मध्य राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा में शामिल क्षेत्र वन क्षेत्र होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वांछित अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदक को पत्र दिनांक 25.05.2015 से लेख किया गया। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वांछित अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8ए(2) के तहत 50 वर्ष की अवधि हेतु खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। आवेदक कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक 378/2017 प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं:-

Keeping in view the fact that an approval has been granted under section 5(1) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 by the Central Government on 16.11.1993, as is evident from Annexure P-3, now in view of the amendment to the aforesaid Act brought into force w.e.f. 27.03.2015 the respondents are directed to atleast execute the agreement with the petitioner as required under the statute before the cutoff-date i.e. 11.01.2017 subject to the outcome of the judicial proceedings and other quasi-judicial proceedings pending in the matter so that ultimately in case the quasi-judicial proceedings or the judicial proceedings are decided in favour of the petitioner, the statutory limitation on the cut-offdate may not come in the way of the petitioner in seeking the benefit of the permission granted by the Central Government.

However, it is clarified that permission to execute the agreement granted by this Court shall not be construed to mean that the petitioner is permitted to carry out the mining activities.

That apart, we further clarify that the decision to be taken and the action thereof shall be subject to out come of any judicial or quasi judicial proceeding or statutory provision that is pending in the matter.

With the aforesaid, the petition stands disposed of.

प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवेदक के पक्ष में वांछित अनुमति जारी नहीं की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन की शर्त अनुसार नियमानुसार अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। अनुबंध निष्पादन के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 378/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2017 में विविध शर्तो के साथ अनुबंध निष्पादन किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में राज्य शासन के पास माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थगन आवेदन प्रस्तुत करने अथवा आदेश के पुनरीक्षण किये जाने हेतु पर्याप्त समय नही है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2017 को जारी किये गये हैं तथा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार अनुबंध निष्पादन की अंतिम तिथि 11.01.2017 है, यद्यपि विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की जा रही है। अतः यह अस्थाई तथा प्रावधिक अनुबंध आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में जारी किये जा रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 09.01.2017 के पालन में निम्न शर्तों के अधीन आवेदक को राज्य शासन द्वारा निर्णित क्षेत्र जिला बालाघाट के ग्राम मोहगांवघाट के खसरा क्र. 396 के रकबा 69.22 एकड़ क्षेत्र अवधि 50 वर्ष खनिज मैगनीज के खनिपट्टा के संबंध में केवल अस्थाई अनुबंध निष्पादित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. उपरोक्त अनुबंध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 09.01.2017 के अधीन होगा। यह पूर्णरूपेण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.01.2017 में उल्लेखित समस्त शर्तो अथवा विभाग द्वारा दायर की जा रही पुनरीक्षण याचिका में पारित किसी भी निर्णय अथवा राज्य शासन द्वारा दायर किसी भी वाद के निर्णय के अधीन होगी। यदि राज्य सरकार कोई निर्णय करती है तथा आवंटन निरस्त करती है तो यह अनुबंध null and void ab initio होगा।
2. आवेदक अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि की खनिज (परमाणु और हाइड्रोजन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 की अनुसूची 04 में विर्निदिष्ट रूप विधान में बैंक प्रत्याभूति के रूप में अथवा

प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध करायेगा। इस कार्यपालन प्रतिभूति का खान विकास और उत्पादन करार में निहित शर्तो और खनन पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। कार्यपालन प्रतिभूति को प्रत्येक 05 वर्ष में समायोजित किया जायेगा, जिससे कि यह अनुमानित संसाधनों के पुनः निर्धारित मूल्य के 0.50 प्रतिशत के सदृश बनी रहे।

3. उपरोक्त शर्त की पूर्ति उपरांत आवेदक को केन्द्रीय सरकार द्वारा विर्निदिष्ट रूप विधान में खान विकास और उत्पादन करार किया जाना होगा।

4. आवेदक द्वारा खनिज (परमाणु तथा हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 की अनुसूची-7 में विनिर्दिष्ट रूप विधान में खनन पट्टा निष्पादित किया जायेगा तथा 11 जनवरी, 2017 को अथवा उससे पहले रजिस्टर किया जायेगा, जिसके न किये जाने पर धारा 10-क की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किये जाने संबंधी अधिकार समपहर्यत हो जायेगा तथा ऐसे मामलों में राज्य सरकार के लिये इस संबंध में कोई भी आदेश जारी करना आज्ञापक नहीं होगा।

5. आवेदक को खनन संक्रिया किये जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के पश्चात खनन संक्रिया आरंभ करने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। उसके पश्चात ही खनन संक्रियाऐं आरंभ की जा सकेगीं।

6. आवेदक द्वारा अनुबंध निष्पादन एवं पंजीयन आदि में व्यय की गई राशि को वापिस प्राप्त किये जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

7. आवेदक के पक्ष में यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति अथवा अन्य वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तब उनके द्वारा निष्पादित अनुबंध शून्य घोषित हो जायेगा।

8. राज्य शासन द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वांछित अनुमति प्राप्त होने पर खनिपट्टा स्वीकृति आदेश एवं अन्य शर्तें अधिरोपित कर जारी किये जा सकेंगे। जिसका पूरक अनुबंध आवेदक को किया जाना होगा।

9. भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा पत्र कमांक 7/55/2016/एम-चार दिनांक 05.01.2017 का पालन करना होगा।

10. उपरोक्त शर्तें मान्य होने पर अनुबंध निष्पादन के पूर्व इसके पालन के संबंध में आवेदक को नियमानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदोपरांत अनुबंध का निष्पादन सुनिश्चित किया जाये तथा निष्पादित अनुबंध की प्रति इस विभाग को प्रेषित की जाये।

11. राज्य सरकार को किसी भी समय तथा कारण से आवंटन निरस्त करने तथा पट्टा अनुबंध को रिवोक करने का एकाधिकार होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे0पी0 श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क्रमांक एफ 2-99/1993/12/2 भोपाल, दिनांकः- 11-1-17

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला - बालाघाट, (म0प्र0) प्रकरण खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 10ए(2)(सी) का है, अतः अनुबंध एवं इसके पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 11.01.2017 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर दिये गये अनुमोदन क्रमांक 5/25/1993/एम-चार दिनांक 16.11.1993 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।
5. कन्ट्रोलर जनरल इंडियन ब्यूरों ऑफ माइंस, इन्द्रा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)
6. महा निदेशक, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, पो. धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड, पिन-826001.
7. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, जबलपुर, म0प्र0।
8. मेसर्स अर्पण फैरो अलायस., गोंदिया रोड़, कोसमी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, PRINCIPAL SEAT JABALPUR

CASE NO. : WP-378-2017 (PENDING)

APPL[illegible] DETAILS:

Application No.: 2292 / 2017 Applicant Name: SATISH KUMAR DIXIT Type: Express

Applied For: (1)Order of date 09-01-2017

PARTY DETAILS:

Petitioner	(1) M/s Arpan Ferro Alloys A Proprietorship Firm, R/o Through The Power Of Attorney Holder Of The Proprietor Anil Kumar Chaturmohta S/o Late Shri I.c. Chaturmohta A/a 62 Ward No 11, Kosmi, Balaghat, District- Balaghat (M.P.)
Respondent	(1) The State Of Madhya Pradesh, R/o Through Its Principal Secretary Mineral Resources Dept. Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (M.P.)
	(2) State Of Madhya Pradesh Through Its Principal Secretary Forest Department, R/o Satpura Bhawan, District- Bhopal (M.P.)
	(3) Collector Balaghat, R/o Balaghat, District- Balaghat (M.P.)

LAST LISTED ON DETAILS:

Judge	HONBLE THE ACTING CHIEF JUSTICE and HONBLE SMT. JUSTICE ANJULI PALO	Date	09-01-2017

EXTRA DETAILS:

Subject Heading/Category /Sub-Category	(1) MINES AND MINERALS-15100 / Mines and Minerals (Regulation and Development)Act 1957-15102/-
Provision of law	
Brief Description of the Judgment/ Order/Award impugned	
Des of Relief Claimed	DIRECTING THE RESPONDENTS TO EXECUTE A FORMAL DEED OF MINING LEASE IN FAVOUR OF THE PETITIONER.

CERTIFICATE:

1 that I [illegible] SINGH (name) am employed as Head Copyist in the High Court of Madhya Pradesh, Main Seat Jabalpur

2 that the High Court of M.P. is engaged in dispensation of Justice and various activities connected there to.

3 that by virtue of my employment as head Copyist, I am authorised to use the computer system in High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur

4 that the computer terminals of the system used by me were functioning regularly to store or process information at all times.

5 that the contents of the certified copy are retrieved from my computer stored in High Court Server which was scanned through original records verified by a digitally signed by the competent authority and certified by me

6 that the above certificate, therefore, in the facts and circumstances of the case, is sufficient compliance of Section 65B of the Evidence Act. The above certified copies/ print outs as taken out from the computer, therefore, can be treated as certified copy

7 Accordingly, I certify that the certified copy of the desired document annexed (1)Order of date 09-01-2017 hereto is/are reproduced or derived from the electronic record which was regularly fed into/transmitted through my computer terminal in High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, in the ordinary course of activities. During the activity the computer system utilized by me were operating properly and there is no distortion in the accuracy of the contents of the certified copy of the desired document.

Head Copyist

FOR COPYING FEES ONLY

(37)

(A 19)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE NO.....201.....

.....Vs.....

DATE OF THE ORDER	ORDER

WP-378-2017

(M/S ARPAN FERRO ALLOYS A PROPRIETORSHIP FIRM Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH)

09-01-2017

Shri Naman Nagrath, learned Senior Counsel with Shri Sanjeev Kumar Mishra, for the petitioner.

Shri Samdarshi Tiwari, learned Dy. Advocate General for the respondents.

Keeping in view the fact that an approval has been granted under Section 5(1) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 by the Central Government on 16.11.1993, as is evident from Annexure P/3, now in view of the amendment to the aforesaid Act brought into force w.e.f. 27.03.2015 the respondents are directed as required under the statute before the cut-off date i.e. 11.01.2017 subject to the outcome of the judicial proceedings and other quasi judicial proceedings pending in the matter so that ultimately in case the quasi judicial proceedings or the judicial proceedings are decided in favour of the petitioner, the statutory limitation on the cut-off date may not come in the way of the petitioner in seeking the benefit of the permission granted by the Central Government.

However, it is clarified that permission to execute the agreement granted by this Court shall not be construed to mean that the petitioner is permitted to carry out the mining activities.

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE NO.....201.....

.....Vs.....

DATE OF THE ORDER	ORDER
	That apart, we further clarify that the decision to be taken and the action thereof shall be subject to outcome of any judicial or quasi judicial proceeding or statutory provision that is pending in the matter. With the aforesaid, the petition stands disposed of. Certified copy today. (RAJENDRA MENON) ACTING CHIEF JUSTICE (SMT. ANJULI PALO) JUDGE vidya TRUE COPY High Court of Madhya Pradesh JABALPUR

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

Annexure 1.10

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE RAVI MALIMATH,

CHIEF JUSTICE

&

HON'BLE SHRI JUSTICE VISHAL MISHRA

ON THE 26th OF SEPTEMBER, 2022

WRIT PETITION No. 10192 of 2021

BETWEEN:-

JAYKAYCEM (CENTRAL) LIMITED, A COMPANY INCORPORATED UNDER THE COMPANIES ACT, 1956, HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT KAMLA TOWER, KANPUR, UTTAR PRADESH, 208 001, THROUGH SHRI ANIL BADGOTRI, AGED ABOUT 54 YEARS, S/O SHRI G.L. BADGOTRI, RESIDNET OF BASANT VIHAR, OPPOSITE PIYUSH SCHOOL KHIRHINI ROAD, KATNI (MADHYA PRADESH)

.....PETITIONER

(BY SHRI NAMAN NAGRATH - SENIOR ADVOCATE WITH SHRI SAHIL BALAIK, SHRI TUSHAR GIRI AND SHRI ARVIND RAY - ADVOCATES)

AND

1. **UNION OF INDIA, THROUGH THE ADDITIONAL SECRETARY, THE ADDITIONAL SECRETARY, MINISTRY OF MINES, INDIAN BUREAU OF MINES, 2ND FLOOR, INDIRA BHAWAN, CIVIL LINES, NAGPUR (MAHARASHTRA)**

2. **THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES, OFFICE OF THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES, INDIAN BUREAU OF MINES, SCHEME NO.11, KAMLA NEHRU NAGAR, JABALPUR (MADHYA PRADESH)**

3. THE STATE OF MADHYA PRADESH, THROUGH DIRECTOR, DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING, 29-A, KHANJI BHAWAN, ARERA HILLS, JAIL ROAD, BHOPAL (MADHYA PRADESH)

.....RESPONDENTS

(SHRI VIKRAM SINGH - ADVOCATE FOR RESPONDENTS NO.1 AND 2 AND SHRI AMIT SETH - DEPUTY ADVOCATE GENERAL FOR RESPONDENT NO.3)

This petition coming on for admission this day, ***Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath, Chief Justice*** *passed the following:*

ORDER

The case of the petitioner is that it was a Public Limited Company incorporated under the Companies Act, 1956. It is engaged in the business of manufacturing of cement. It is in the process of setting up an integrated cement plant in Panna District, Madhya Pradesh. On 21.08.2008, the petitioner submitted an application under Section 10 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (for short "the MMDR Act") for grant of Prospecting Licence for Limestone mining in an area admeasuring 3703.00 Hectares in Village Kamtana, Kakra, Saptai, Judi, Devri, Purohit, Devri Tahsil, Amanganj (Kakra Mining Block). On 15.03.2010, the State of Madhya Pradesh passed an order granting a Prospecting Licence to the petitioner to an extent of 3513.75 Hectares, for a period of two years subject to the various conditions. On completion of the various requirements of the said order, by the order dated 28.06.2010 a Prospecting Licence Deed for the areas mentioned therein was executed with a validity up to 14.06.2012.

2. Thereafter, the petitioner undertook the prospecting operations over the area in question. On completion of the prospecting operations, the petitioner submitted an application for grant of mining lease. Thereafter, the State of Madhya Pradesh accepted the petitioner's application and directed the

petitioner to submit a duly approved mining plan within a period of six months from 10.07.2014. Extension of time was granted. Thereafter, the mining plan was submitted, which was approved by the State on 03.08.2015. The petitioner, vide order dated 17.03.2016, was called upon to execute the mining lease for the area in question within a period of six months after complying with the various conditions. The said order was modified by the Government of Madhya Pradesh in view of Rule of 7 of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (for short " the MCR Rules, 2016") where the mining lease was to be executed within a period of 90 days on fulfilling of various conditions. Thereafter a bank guarantee was submitted for a sum of about 0.5% of the value of the estimated resources at about Rs.53 Crores. A sum of Rs.86,30,000/- was deposited. A mine development and production agreement was executed with the State Government. Environmental Clearance was obtained. Thereafter, on 09.09.2020 the State of Madhya Pradesh executed a mining lease for Kakra Mining Block i.e the land in question. Thereafter, there were various communications between the Central Government and the State Government. Ultimately, the respondent No.2 passed the impugned order revoking the approval of the abovesaid mining plan. Questioning the same, the instant petition was filed.

3. An interim order of status quo was granted by this Court by the order dated 28.06.2021. Thereafter, an application was filed seeking to proceed in the mining activities. By the order dated 10.08.2021, it was held that no clarification is required as there is no ambiguity in the said order. The same was challenged before the Hon'ble Supreme Court in Special Leave Petition (Civil) No.20103 of 2021 [Jaykaycem (Central) Ltd vs. Union of India and others]. Vide order dated 07.01.2022 the Special Leave Petition was disposed off with a request to the High Court to dispose off the petition within a period

of four months from the said order. Thereafter, the matter was listed for consideration before this Court. The matter was adjourned at the request of the counsel for the petitioner on 16.03.2022. On 16.06.2022 learned counsel for the petitioner was absent. Vide order dated 21.06.2022, the matter was adjourned in view of the adjustment note. On 23.08.2022, counsel for the petitioner was absent. Thereafter, the matter has been taken up for final hearing.

4. Shri Naman Nagrath, learned senior counsel appearing for the petitioner's counsel contends that the impugned order passed by the respondents is bad on facts and in law, hence is liable to be set aside. That the respondents have no source or power to issue the impugned order. The respondents have exercised their powers under Section 5(2)(b) of the MMDR Act. The same is alien to the facts and circumstances involved. The respondents have no power to issue the same. Even otherwise, he contends that the petitioner is governed by the provision of Section 10A(2)(b) of the MMDR said Act. However, what is ostensibly being contended by the respondents is the applicability of Clause 10A(2)(c) of the Act. Hence, it is contended that the impugned order is liable to be set aside. He further contends that the said issue is no more *res integra* in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Bhushan Power & Steel Ltd. Vs. State of Odisha, reported in (2017) 2 SCC 125.

5. The same is disputed by Shri Vikram Singh, learned counsel appearing for respondents No.1 and 2. He supports the impugned order and submits that there was no error committed by the respondents that calls for any interference. Contentions have been advanced on the merits of the matter.

6. Shri Amit Seth, learned Deputy Advocate General appeared for the respondent No.3/State. He has also filed his reply. He supports the case of the writ petitioner to the extent that the provision of law as contended by the

respondents is incorrect. By relying on the statement of objections, he pleads that the action of the State is appropriate and in tune with the relevant Acts and the Rules. Therefore, he pleads that the petition be dismissed.

7. Heard learned counsels.

8. The impugned order passed by the respondent No.2, as stated therein is in exercise of the powers contained in Section 5(2)(b) of the MMDR Act. In terms whereof, the mining plan was revoked by the impugned order. Section 5(2)(b) of the MMDR Act reads as follows:-

> *"5. Restrictions on the grant of prospecting licences or mining leases:-*
> *** *** ***
> *(2) No mining lease shall be granted by the State Government unless it is satisfied that—*
> *** *** ***
> *(b) there is mining plan duly approved by the Central Government, or by the State Government, in respect of such category of mines as may be specified by the Central Government, for the development of mineral deposits in the area concerned.*
>
> *(Provided that a mining lease may be granted upon the filing of a mining plan in accordance with a system established by the State Government for preparation, certification, and monitoring of such plan, with the approval of the Central Government)"*

9. On specifically being questioned, learned counsel for respondents No.1 and 2 fairly contends that the provisions of the said Rules do not empower the respondents to issue the said order. That there is no power as vested under Section 5(2)(b) of the MMDR Act for issuance of the said order. Apparently a wrong provision of law has been invoked. Therefore the respondents had no power to issue the impugned order. Therefore, we do not find that the source of power as exercised by the respondents No.1 and 2 has any nexus to the facts and circumstances of the case.

10. In absence of any source of power, the impugned order becomes unsustainable. However, it is orally contended by the learned counsel for the respondents No.1 and 2 that in terms of Section 21 of the General Clauses Act, 1897, the respondents have the power to issue the impugned order. Section 21 of the General Clauses Act, reads as follows:-

> *"21. Power to issue, to include power to add to, amend, vary or rescind notifications, orders, rules or bye-laws. – Where, by any Central Act or Regulations a power to issue notifications, orders, rules or bye-laws is conferred, then that power includes a power, exercisable in the like manner and subject to the like sanction and conditions (if any), to add to, amend, vary or rescind any notifications, orders, rules or bye-laws so issued."*

11. The Hon'ble Supreme Court in the case of Chintpurni Medical College and Hospital and Another vs. State of Punjab and others reported in (2018) 15 SCC 1 while considering the said contention held in paragraphs 26, 27 and 32 that when the statutory authority has to perform a particular duty under the statute, Section 21 of the General Clauses Act has no application and confers no powers to review such an act. That the powers to review/recall could be specifically provided under the particular section under which the power is sought to be exercised. Therefore, Section 21 of the General Clauses Act cannot be read to the power of respondents in passing the said order. Therefore, on this ground also, we are of the view that the contentions of the respondents of taking aid of Section 21 of the General Clauses Act, in our considered view, will not have any application to the facts of this case. Even though various contentions were advanced, so far as the merits of the matter is concerned, we do not think it appropriate to go into the same.

12. We are of the view that it is not a question that arises for consideration by this Court. The question of interpretation of the various provisions of law

that are being argued by each one of the counsels cannot form the subject matter of this petition. The impugned order only narrates the withdrawal of the mining plans in exercise of the power under Section 5(2)(b) of the MMDR Act. Since we have already come to the conclusion that the respondents had no power to issue the said impugned order under Section 5(2)(b) of the MMDR Act, we are of the view that the said order becomes unsustainable in law. Even otherwise, we are unable to get any satisfactory answer from respondents No.1 and 2 to sustain the impugned order under Section 5(2)(b) of the MMDR Act.

13. Consequently, the petition is allowed. The order dated 08.06.2021 passed by the respondent No.2 is quashed. However, we would like to clarify that the quashing of the said order will not come in the way of the respondents to pass any such order in accordance with law.

(RAVI MALIMATH)
CHIEF JUSTICE

(VISHAL MISHRA)
JUDGE

prar

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
Digitally signed by PRARTHANA SURYAVANSHI
Date: 2022.09.30 14:57:59 +05'30'

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांकः- 22/11/2019

क्रमांक- एफ 2-99/1993/12/2 :- मेसर्स अर्पण फैरौ अलायस के पक्ष में जिला बालाघाट तहसील बारासिवनी के ग्राम मोहगांवघाट के खसरा क्र. 396 के रकबा 69.22 एकड़ (रकबा 28.012 हे.) क्षेत्र पर मैगनीज खनिज का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 5/25/1993/एम-चार दिनांक 16.11.1993 से धारा 5(1) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके पालन में राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2-99/1993/12/2 दिनांक 24.05.1994 से खनिपट्टा स्वीकृत किया गया था। आवेदक द्वारा अनुबंध निष्पादन की समस्त औपचारिकताए पूर्ण कर दी गई थी। परंतु अनुबंध निष्पादन नहीं हो सका। इसका कारण यह था कि राज्य शासन द्वारा यह निर्णय राजस्व भूमि प्रतिवेदित होने के आधार पर लिया गया था। परंतु यह क्षेत्र वन कक्ष क्र. 807 का भाग होने के कारण अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संबंधित क्षेत्र के संबंध में राजस्व भूमि मान्य करते हुये दिनांक 16.11.1993 से धारा 5(1) के तहत दिये गये अनुमोदन को वन क्षेत्र मान्य करते हुये पुनरीक्षित अनुमोदन दिये जाने हेतु पत्र दिनांक 15.01.2014 से लेख किया गया। आज दिनांक तक भारत सरकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका है। इसी मध्य राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा में शामिल क्षेत्र वन क्षेत्र होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वांछित अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदक को पत्र क्रमांक एफ 2-99/1993/12/2 दिनांक 25.05.2015 से सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वांछित अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदक कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 378/2017 प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 के पालन में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2-99/1993/12/2 दिनांक 11.01.2017 से आवेदक मेसर्स अर्पण फैरौ अलायस के पक्ष में जिला बालाघाट तहसील बारासिवनी के ग्राम मोहगांवघाट के खसरा क्र. 396 के रकबा 69.22 एकड़ (रकबा 28.012 हे.) क्षेत्र पर खनिज मैगनीज हेतु खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8ए(2) के तहत 50 वर्ष के लिये सशर्त अस्थाई अनुबंध निष्पादन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई। उक्त आदेश के पालन में आवेदक द्वारा खनिपट्टा का अवधि 11.01.2017 से 10.01.2067 तक अर्थात् 50 वर्ष का अनुबंध निष्पादन कराया गया।

यह कि आवेदक मेसर्स अर्पण फैरौ अलायस द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन एवं पर्यावरण सम्मति संबंधी औपचारिकताऐं पूर्ण न हो पाने के कारण खनन संक्रियाऐं प्रारंभ नहीं किये जाने का लेख करते हुए दिनांक 20.09.2018 से खनिज (परमाणु तथा हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 20(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए नियम 20(5) के

प्रावधानों के अधीन रूपये 1,00,000/- की फीस पट्टेधारी द्वारा ई-चालान कमांक 75 दिनांक 06.02.2019 द्वारा जमा कर खनन संकियाऐं प्रारंभ करने हेतु 02 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि की अनुमति प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया।

राज्य शासन द्वारा आवेदक मेसर्स अर्पण फैरौ अलायस द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20.09.2018 के निराकरण हेतु प्रकरण में दिनांक 22.10.2019 को अंतिम सुनवाई नियत की गई। नियत सुनवाई में आवेदक मेसर्स अर्पण फैरौ अलायस की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार चतुरमोहता तथा उनके अधिवक्ता श्री आर. ए. बराइपाण्डे एवं शासन के पक्ष समर्थन हेतु श्री प्रकाश सिंह पन्द्रे, उप संचालक (ख.प्र.) उपस्थित हुये। उन्हें सुना गया। उनके द्वारा लिखित जबाव एवं मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रमुख रूप से स्पष्ट किया गया कि वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव कमांक एफ.पी./एन.पी./एम.आई.एन./19894/2016 दिनांक 15.07.2016 को वन विभाग में जमा कराया गया। इसी प्रकार पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव कमांक एस.आई.ए./एम.पी./एम.आई.एन./58248/2016 दिनांक 09.08.2016 को पर्यावरण विभाग में जमा कराया गया है। उपरोक्त प्रस्तावों पर वांछित अनुमतियां आज दिनांक तक अपेक्षित है, संबंधित कार्यवाही प्रचलन में है, जिस पर पट्टेदारी का कोई नियंत्रण नहीं है। वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग से आवश्यक वांछित अनुमति / सम्मति प्राप्त होते ही विभाग को प्रस्तुत कर दी जायेगी। कंपनी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि आगामी दो वर्षो में सभी गतिविधियां पूर्ण की जाकर खनन संकियाऐं प्रारंभ की जायेगी। अतः खनन संकियाऐं प्रारंभ करने हेतु दो वर्ष की अतिरिक्त समयावधि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा पूर्ण विचारोपरांत खनिज (परमाणु तथा हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 20(6) के अधीन आवेदक मेसर्स अर्पण फैरौ अलायस के पक्ष में जिला बालाघाट तहसील बारासिवनी के ग्राम मोहगांवघाट के खसरा क्र. 396 के रकबा 69.22 एकड़ (रकबा 28.012 हे.) क्षेत्र पर खनिज मैगनीज हेतु अवधि 11.01.2017 से 10.01.2067 तक अर्थात् 50 वर्ष के लिये स्वीकृत खनिपट्टा में दिनांक 11.01.2019 से 10.01.2021 तक अर्थात् 02 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक वांछित अनुमति / सम्मति प्राप्त कर खनन संकियाऐं प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय आदेश दिनांक 11.01.2017 में उल्लेखित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृ.क्र. एफ 2-99/1993/12/2 भोपाल, दिनाँक - 22/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय समाघात प्राधिकरण (सिया), पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश।
5. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंधन), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट, मध्यप्रदेश।
7. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वन मंडल, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
8. महानिदेशक, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, पो. धनबाद, जिला धनबाद (झारखण्ड)।
9. कन्ट्रोलर जनरल, आई.बी.एम., इंद्रा भवन, सिविल लाईस, नागपुर, महाराष्ट्र।
10. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, आई.बी.एम., जबलपुर, मध्यप्रदेश।
11. मेसर्स अर्पण फेरो अलायस, गोंदिया रोड़, कोसमी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail - modgmbal@mp.gov.in Ph.No. 07632-241683

क्रमांक/ 144 /खनिज/19 बालाघाट दिनांक 07 / 01 /2019

प्रति,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो
जबलपुर (म.प्र.)

विषय- ग्राम मोहगांव वन कक्ष क्रमांक 807, 809 भाग रकबा 28.02 हे. खनिज मैगनीज ओर खनिपट्टा के संबंध मे जानकारी बावत्।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक MP/Balaghat/Manganese/MPLN/MOD-19/18-19/5088 जबलपुर दिनांक 07/06/2018

--::::::::::000:::::::::--

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य मे लेख है कि म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-99/1993/12/2 दिनांक 11/01/2017 के पालन मे तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 378/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 09/01/2017 मे निहित शर्तो के अधीन खनिपट्टा का पंजीयन निर्गमन तिथि 11/01/2017 समय 11:01:52 PM को प्रचलित थी। अतः अनुबंध वैध है।

सूचनार्थ प्रेषित।

खनि. अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail - modgmbal@mp.gov.in Ph.No. 07632-241683

क्रमांक / /ख0लि0–02/2021 बालाघाट दिनांक 18/6/2021

प्रति,

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
29–ए अरेरा हिल्स खनिज भवन
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– Grant of Mining Lease (ML) for mineral Managanese over an area of 28.02 hectares situated in village Mohaganonghat, Tehsil Kherlanji District Balaghat (M.P.) in favour of M/s. Arpan Ferro Alloys, Balaghat reg.

संदर्भ :– आपका का पत्र क्रमांक 7032 दिनांक 16.06.2021 एवं भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर का पत्र दिनांक 20.05.2021

—:::::::::::::000:::::::::::::—

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2–99/1993/12/2 दिनांक 11.01.2017 के अनुसार, ग्राम मोहगांवघाट तह. खैरलांजी वन कक्ष भाग 807, 809 रकबा 28.02 हे. क्षेत्र खनिज मैगनीज ओर का खनिपट्टा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 8ए(2) के तहत् 50 वर्ष की अवधि के लिये मेसर्स अर्पण फेरो एलायस निवासी कोसमी जिला बालाघाट को स्वीकृत किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे दायर याचिका क्रमांक 378/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 09.01.2017 मे विविध शर्तो के तहत् अनुबंध निष्पादन किये जाने के निर्देश जारी किये गये। जिसके तहत् अनुबंध निष्पादन की अंतिम तिथि 11.01.2017 थी। आवेदक को खनिज मैगनीज ओर खनिपट्टा के संबंध मे निहित शर्तो के अधीन केवल अस्थायी अनुबंध निष्पादन किये जाने की अनुमति सशर्त प्रदान की गई। माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानो को शिथिल करते हुये आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त आदेश के परिपालन मे दिनांक 11.01.2017 को खनिपट्टा का पंजीयन निर्गमन तिथि 11.01.2017 समय 11:01:52 पी.एम. को प्रचलित थी। किन्तु ई–पंजीयन के सर्वर मे बाधा/तकनीकि खामी होने के फलस्वरूप निष्पादन मे समय व्यतित् हुआ। अतः अनुबंध वैध है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

सही
प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा)
प्रभारी अधिकारी
सहा. कलेक्टर बालाघाट
खनिज शाखा बालाघाट

पृ.क्रमांक 759-A /ख0लि0–02/2021 बालाघाट दिनांक 18/6/2021

प्रतिलिपि–

1– महानियत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ।

2– क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो , योजना क्रमांक 11, कमला नेहरू नगर, जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

3– मेसर्स अर्पण फेरो एलायस साकिन कोसमी जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा)
प्रभारी अधिकारी
सहा. कलेक्टर बालाघाट
खनिज शाखा बालाघाट

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29–ए "खनिज भवन" अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स – 0755–2551795
E-mail - dirgeomn@nic.in

क्रमाँक – भोपाल दिनाँक – 19/7/21

प्रति

क्षेत्रीय खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, योजना क्रमाँक 11,
कमला नेहरू नगर, जबलपुर (म.प्र.)।

विषय :– Grant of Mining Lease (ML) for mineral management over an area of 28.02 hectares situated in village Mohjagaonghat, Tehsil Kherlanji District Balaghat (M.P.) in favour of M/s Arpan Fero Alloys, Balaghat reg.

संदर्भ :– भारत सरकार, खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर का पत्र क्रमाँक MP/Balaghat/Manganese/MPLN/MOD-35/2019-20/4824 जबलपुर, दिनाँक 20/05/2021.

———

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट म.प्र. के पत्र क्रमाँक 795/ख.लि./02/2021 बालाघाट, दिनाँक 18/06/2021 की प्रति संलग्न है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

संचालक

पृ. क्रमाँक – 9846-48 भोपाल दिनाँक – 19/7/21
प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, नागपुर महाराष्ट्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अर्पण फेरो एलायस साकिन कोसमी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय :

F-2-99/93/12/2

जिला बालाघाट के ग्राम मोहगॉवघाट के रकबा–69.22 एकड़ पर मैगनीज खनिज का उत्खनिपट्टा –मेसर्स अर्पण फेरो अलायज।

पूर्व पृष्ठ से :–

विभाग/पर्यावरण विभाग से आवश्यक वांछित अनुमति/सम्मति प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

नस्ती में संधारित समस्त अभिलेखों का अवलोकन/परीक्षण, शासन का श्री प्रकाश सिंह पन्द्रे, उप संचालक (ख.प्र.) द्वारा प्रस्तुत पक्ष का श्रवण तथा आवेदक मेसर्स अर्पण फेरो अलायज के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्को का श्रवण एवं लिखित तर्क का अवलोकन/परीक्षण करने के बाद यह पाया कि :–

आवेदक द्वारा दिनांक 24.08.92 को जिला–बालाघाट के ग्राम मोहगांवघाट के रकबा–69.22 एकड़ क्षेत्र पर मैगनीज ओर खनिज के लिए खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.11.93 से तत्समय प्रचलित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया। राज्य शासन द्वारा ज्ञापन कमांक 2–99/93/12/2 दिनांक 04.12.93 से आवेदक को भारतीय खान ब्यूरों से अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। आवेदक ने भारतीय खान ब्यूरों से ज्ञापन कमांक BGT/MN/MPLN-357/NGP दिनांक 09.05.94 से अनुमोदित माईनिंग प्लान राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 24.05.94 प्रश्नांकित क्षेत्र पर 20 वर्ष की अवधि हेतु मैगनीज ओर खनिज के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किया गया। आवेदक द्वारा नियमानुसार अनुबंध निष्पादन के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 10.06.94 को अनुबंध हेतु अभिलेख कलेक्टर कार्यालय, बालाघाट में प्रस्तुत किये परन्तु कलेक्टर, बालाघाट ने अनुबंध निष्पादन नहीं करते हुए ज्ञापन कमांक 13982 दिनांक 17.10.95 से राज्य शासन को लेख किया कि वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) द्वारा अवगत कराया गया कि खनिपट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र, वन क्षेत्र है। नस्ती के अनुसार वन क्षेत्र है खनिपट्टा स्वीकृति आदेश को एक वर्ष से अधिक हो चुका है, अतः स्वीकृत क्षेत्र राजस्व भूमि होने की स्थिति में अनुबंध हेतु शासन की अनुमति आवश्यक है। कलेक्टर के ज्ञापन दिनांक 17.10.95 पर दिनांक 30.05.95 से 06.07.2007 तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर, बालाघाट के द्वारा पुनः राज्य शासन को पत्र कमांक 5568 दिनांक 20.06.2007 लेख किया गया, जिसके संदर्भ में राज्य शासन द्वारा समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 27.08.2008 से

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

छब्बीस-२ सचिवालय

F-2-99/93/12/2

का विभाग

विषय : **जिला बालाघाट के ग्राम मोहगॉवघाट के रकबा–69.22 एकड़ पर मैगनीज खनिज का उत्खनिपट्टा –मेसर्स अर्पण फेरो अलायज।**

पूर्व पृष्ठ से :–

कलेक्टर, बालाघाट को निर्देशित किया गया कि यदि स्वीकृत क्षेत्र वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं है अथवा मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार वन भूमि के रूप में परिभाषित नहीं है तो स्वीकृत क्षेत्र का नियमानुसार अनुबंध निष्पादन कराया जाकर तत्काल खनन कार्य की अनुमति दी जाये। राज्य शासन के निर्देशों के बावजूद भी कलेक्टर, बालाघाट द्वारा अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया। आवेदक के निवेदन पर तत्कालीन मंत्रीजी द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर राज्य शासन द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में राज्य शासन के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 15.01.14 से प्रकरण की वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली से अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत पुनः पूर्वानुमोदन प्रदान किये जाने हेतु लेख किया गया यद्यपि भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही दिनांक 16.11.93 को उक्त अनुमोदन प्रदाय किया जा चुका था। राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 15.01.14 के संदर्भ में भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन दिनांक 26.09.14 से राज्य शासन को विषयांकित प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 31 (1) के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु लेख किया। भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 26.09.14 के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा ज्ञापन दिनांक 25.05.15 से भारत सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है कि खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 31 में अनुबंध निष्पादन हेतु राज्य सरकार अतिरिक्त समयावधि प्रदान कर सकती है इसकी कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 25.05.15 से आवेदक को स्वीकृत क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावशील होने के कारण विभागीय परिपत्र दिनांक 22.06.2006 के अनुसार वनभूमि व्यपवर्तन किये जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

जिसके अनुक्रम में आवेदक द्वारा वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। कलेक्टर, बालाघाट द्वारा ज्ञापन दिनांक 11.07.16 से आवेदक के पक्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुमति दिये जाने हेतु अनापत्ति वन मण्डलाधिकारी, बालाघाट को दी। आवेदक पट्टेदार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदन प्रस्ताव कमांक FP/NP/MIN/19894/2016 दिनांक 15.07.16 को जमा कराया गया।

जिला बालाघाट के ग्राम मोहगॉवघाट के रकबा–69.22 एकड़ पर मैगनीज खनिज का उत्खनिपट्टा –मेसर्स अर्पण फेरो अलायज।

पूर्व पृष्ठ से :–

इसी प्रकार पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/MIN/58248/2016 दिनांक 09.08.16 को जमा कराया गया।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार देश में लंबित खनिपट्टा प्रकरण दिनांक 11.01.17 तक निराकृत होना चाहिये थे। नियत समय–सीमा 11.01.17 निकट होने के कारण आवेदक द्वारा मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र. में याचिका क्रमांक 378/2017 दायर की गई जिस पर मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.17 से राज्य शासन को कट–ऑफ डेट 11.01.17 के पूर्व प्रकरण में अनुबंध निष्पादन के निर्देश दिये जिसके पालन में राज्य शासन ने ज्ञापन दिनांक 11.01.17 से कलेक्टर, बालाघाट को अनुबंध की कार्यवाही दिनांक 11.01.17 के पूर्व करने के निर्देश दिये। तदनुसार दिनांक 11.01.17 को अनुबंध का निष्पादन किया गया। इस क्रम में आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 27.09.16 के संदर्भ में आवेदक को प्रपत्र –2 में प्रमाण पत्र क्रमांक–8016 दिनांक 20.01.17 जिला वन अधिकार समिति का सहमति–पत्र दिया। वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य), बालाघाट के ज्ञापन दिनांक 27.04.17 के आधार पर आवेदक द्वारा पंजीयन शुल्क रूपये–5000/– तथा प्रोसेशिंग शुल्क रूपये–1,50,000/– डी. डी. दिनांक 27.04.17 के माध्यम से जमा कराया गया है। आवेदक द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जिला–बालाघाट के ग्राम असरमा की 28.868 हे. भूमि वन विभाग को सौंपना प्रस्तावित किया था किन्तु वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य), वन मण्डल, बालाघाट द्वारा पत्र दिनांक 16.06.17 से प्रस्तावित भूमि के स्थान पर अन्य भूमि प्रस्तावित करने हेतु लिखा। अंततः पट्टेदार द्वारा वन विभाग को वनभूमि के एवज ग्राम ढीपुर, जिला–बालाघाट के अंतर्गत रकबा–28.326 हे. प्रस्तावित किया गया जिसकी दस वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है। विषयांकित प्रकरण में राज्य शासन के आदेश दिनांक 24.05.94 से खनिपट्टा आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किया था जिसे आज दिनांक तक राज्य शासन के किसी भी आदेश द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। विषयांकित खनिपट्टा संशोधन अधिनियम, 2015 के जारी होकर प्रभावशील होने की दिनांक 12.01.15 से पूर्व अर्थात 24.05.94 का है। अतः इस पर संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 10 A(2)(C) लागू नहीं किया जा सकता। अन्यथा भी अधिनियम की

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

विषय : जिला बालाघाट के ग्राम मोहगॉवघाट के रकबा–69.22 एकड़ पर मैगनीज खनिज का उत्खनिपट्टा –मेसर्स अर्पण फेरो अलायज।

पूर्व पृष्ठ से :–

धारा 10 A(2)(C) के अनुसार अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 12.01.15 के पूर्व अनुदत्त खनिपट्टों के संबंध में किए गए अनुबंध शून्य हो जाने अथवा खनिपट्टा स्वीकृति आदेश निष्प्रभावी होने का भी प्रावधान नहीं है।

विषयांकित खनिपट्टा संशोधन अधिनियम, 2015 के जारी होकर प्रभावशील होने की दिनांक से पूर्व का अर्थात दिनांक 24.05.94 (अनुदत्त दिनांक) का है। अतः इस प्रकरण पर तत्समय प्रचलित खनि रियायत नियम, 1960 के प्रावधान लागू होते है। अर्थात खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 27 (3) के प्रावधानों के तहत ही राज्य सरकार या तो केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन या केन्द्र सरकार के अनुरोध पर अतिरिक्त अधिरोपित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के स्वीकृति आदेश दिनांक 24.05.94 एवं किये गए अनुबंध दिनांक 11.01.17 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान के तहत अनुमति प्रस्तुत करने की कोई शर्त नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि खान एव खनिज (विकास एव विनियम) अधिनियम, 1957 अथवा प्रचलित खनि रियायत अन्य नियमों में कहीं भी वनभूमि के परिप्रेक्ष्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वांछित अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु स्पष्ट समय–सीमा निर्धारित नहीं है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में पट्टेदार द्वारा किसी भी स्तर पर कोई भी विलंब नही किया गया है। वांछित अनुमतियां प्राप्त किये जाने हेतु समय–समय पर समुचित कार्यवाही की गई है जो कमशः वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग में लंबित है, संबंधित कार्यवाही प्रचलन में है जिस पर पट्टेधारी का कोई वश नहीं हैं। पट्टेदार के प्रकरण के समान प्रकृति के प्रकरणों में महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य शासन द्वारा निर्णय लेते हुए स्वीकृत खनिपट्टे के संबंध में अनुबंध निष्पादन के उपरांत खनन संकियाएं प्रारम्भ करने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 Environment Protection Act, 1986 and Rules 1986, Environmental Impact Assessment Notification 1994 तथा समय–समय पर किये गए संशोधनों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से आवश्यक सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। पट्टेदार द्वारा भी आवश्यक सम्मतियां/अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु त्वरित कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है। अतः पट्टेदार के प्रकरण में पूर्व में जारी किए गए राज्य शासन के आदेश दिनांक 11.01.17 को वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय :

F-2-99/93/12/2

जिला बालाघाट के ग्राम मोहगॉवघाट के रकबा–69.22 एकड़ पर मैगनीज खनिज का उत्खनिपट्टा –मेसर्स अर्पण फेरो अलायज।

पूर्व पृष्ठ से :–

दिनांक 11.01.17 को जारी राज्य शासन के आदेश दिनांक 11.01.17 को यथावत रखा जाता है। पट्टेदार को निर्देशित किया जाए कि प्रश्नांकित खनिपट्टे में खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 Environment Protection Act, 1986 and Rules 1986, Environmental Impact Assessment Notification 1994 तथा समय–समय पर किये गए संशोधनों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से आवश्यक सम्मतियां/अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(प्रदीप जायसवाल)
मंत्री
खनिज साधन विभाग

प्रमुख सचिव,
खनिज साधन विभाग

जावक क्र. 6623 मंत्री/ख.सा./2019
दिनांक 23.10.19

1580/PS/MRD/15
(8/11/19)

18/11

DD(P)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग.

GEOHYDROLOGICAL STUDIES OF THE MINE AREA OF M/S ARPAN FERRO ALLOYS, MOHAGAONGHAT MANGANESE ORE MINE, MOHAGAONGHAT, KATANGI, BALAGHAT M.P.

AND

CONSERVATION PLAN OF SURROUNDING WATER RESERVOIR

A REPORT

SUBMITTED

BY

DR. SANTOSH SAKSENA

SECRETARY

GEOLOGICAL ASSOCIATION AND RESEARCH CENTER

(REGD. NO. JB/748)

BALAGHAT M.P.

2022

GEOLOGICAL ASSOCIATION & RESEARCH CENTRE

(Associated with J.S.T. Govt. P.G. College Balaghat)
(Regd. No. JB. 748)

D.A. Museum
Opp. Circuit House
BALAGHAT (M.P.)
481001

Mobile- 07999705284/09406751365
e-mail- garc.bgt@rediffmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that the report of "Geohydrological studies of the mine area of M/S Arpan Ferro-alloys, Mohagaonghat manganese ore Mine, Mohagaonghat, Katangi, Balaghat"has been prepared by Geological Association and Research Center under my guidance.

The field work, collection of well inventory data, rock and water samples etc. has been done by Shri Akhilesh Patle, Shri Manish Invati, Shri Sourabh Uikey and Shri Venkatesh Gedam, all members of GARC.

The maps have been generated by Shri Ankit Upadhyay, GIS and Remote Sensing Expert by Arc GIS 10.1 software.

The entire work has been done under my supervision and monitoring.

(Dr. Santosh Saksena)

Secretary
Geological Association & Research Centre
D.A. Museum,opp.Circuit House
BALAGHAT (M.P.) 481001

S.No.	CONTENTS	Page No.
1	Introduction	1
2	Physiography	1
3	Climate	2
4	Soils	2
5	Land use/ Land cover	2
6	Drainage	3
7	Geology	3
8	Geomorphology	4
9	Groundwater occurrence and movement	4
10	Groundwater inventory	6
11	Groundwater features	7
12	Quality of water	8
13	Discussion	10
14	Lineaments	10
15	GIS studies	11
16	Groundwater potentials	12
17	Conservation plan of surrounding water reservoir	13
18	Conclusion	15

S.No.	LIST IF MAPS	After Page No.
1	Location map	1
2	Topographic map	1
3	Settlement map	2
4	Physiographic map	3
5	Drainage and surface bodies map	4
6	Geomorphological map	4
7	Well location map	7
8	Well location and water table contour map	7
9	Hydraulic gradient map	7
10	Lineament map	10
11	Superimposed map of geomorphology and water table contours	12
12	Superimposed map of lineaments, drainage and surface water bodies	12
13	Superimposed map of lineaments, water table contours and hydraulic gradients	12
14	Map of water tank near lease area boundary	13

INTRODUCTION

Water is a prime natural resource, a basic need and a precious national asset. It is an important natural resource, essential to sustain life on Earth. It is one of the principal elements, which influence economic, industrial and agricultural growth.

The study area (Latitude $21^0$34'10"N-$21^0$38'20"N Longitude $79^0$45'50"E-$79^0$50'5"E) is covered by Survey of India Toposheet No. 55 O/14. The area selected for study is number of times greater than the total area of the mine, so that a complete picture of the geomorphology, geology, drainage, lineaments etc. can be drawn in order to appraise the geohydrological conditions.

Groundwater conditions are very poor in this area and because of paucity of irrigation facilities, the villagers have to depend solely on rainfall. One tank is adjoining the mines area which can be developed to provide sufficient water for irrigation. A plan of its development has been formulated.

The study area is approachable by all weather roads from Waraseoni and Katangi.

PHYSIOGRAPHY

The study area has a long hill range in the mine area, extending from northeast to southwest and tapering in southwest. The surrounding area is almost plain, which has paddy fields.

Beyond the mine area, the entire northwest to southwest area has sloppy and hilly part and drainage from this area is towards south where numbers of tanks have been developed.

LOCATION MAP OF STUDY AREA

VILLAGE – MOHGAONGHAT, TEH – KHAIRLANJI, DISTT. BALAGHAT

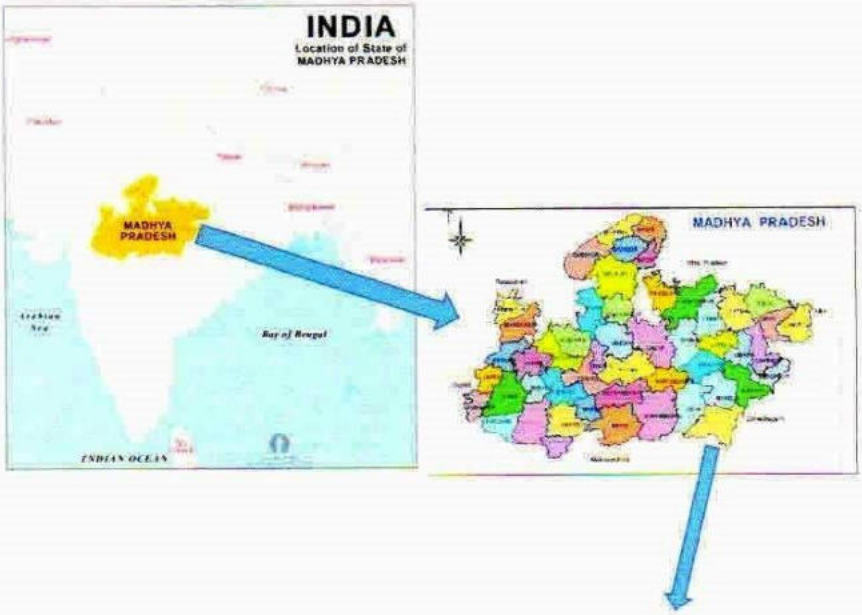

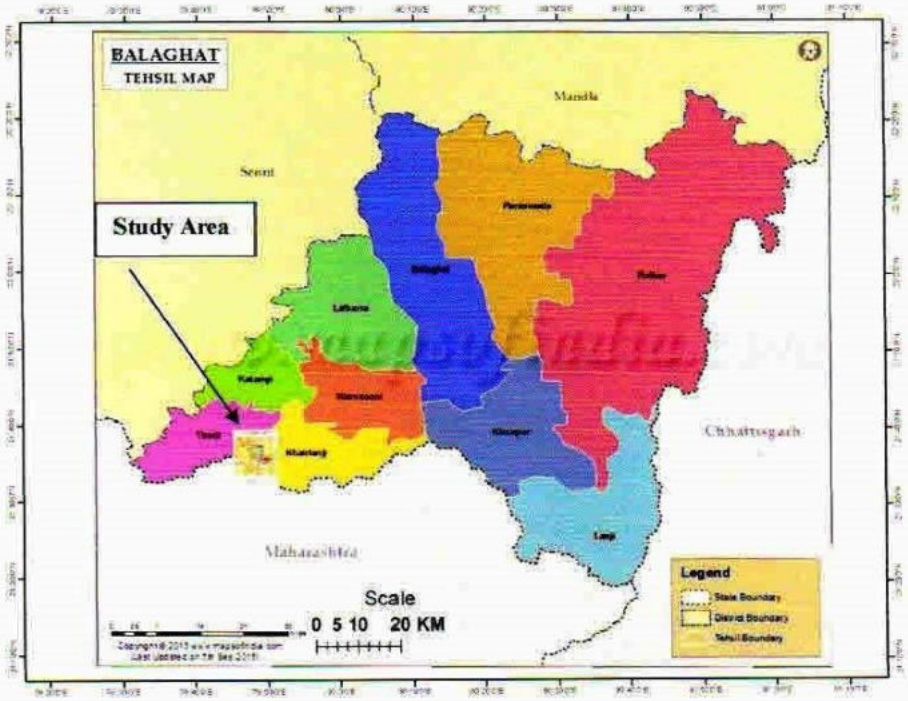

TOPOGRAPHICAL MAP OF STUDY AREA
VILLAGE - MOHGAONGHAT, DISTRICT - BALAGHAT
TOPOSHEET NO. 55 O/14

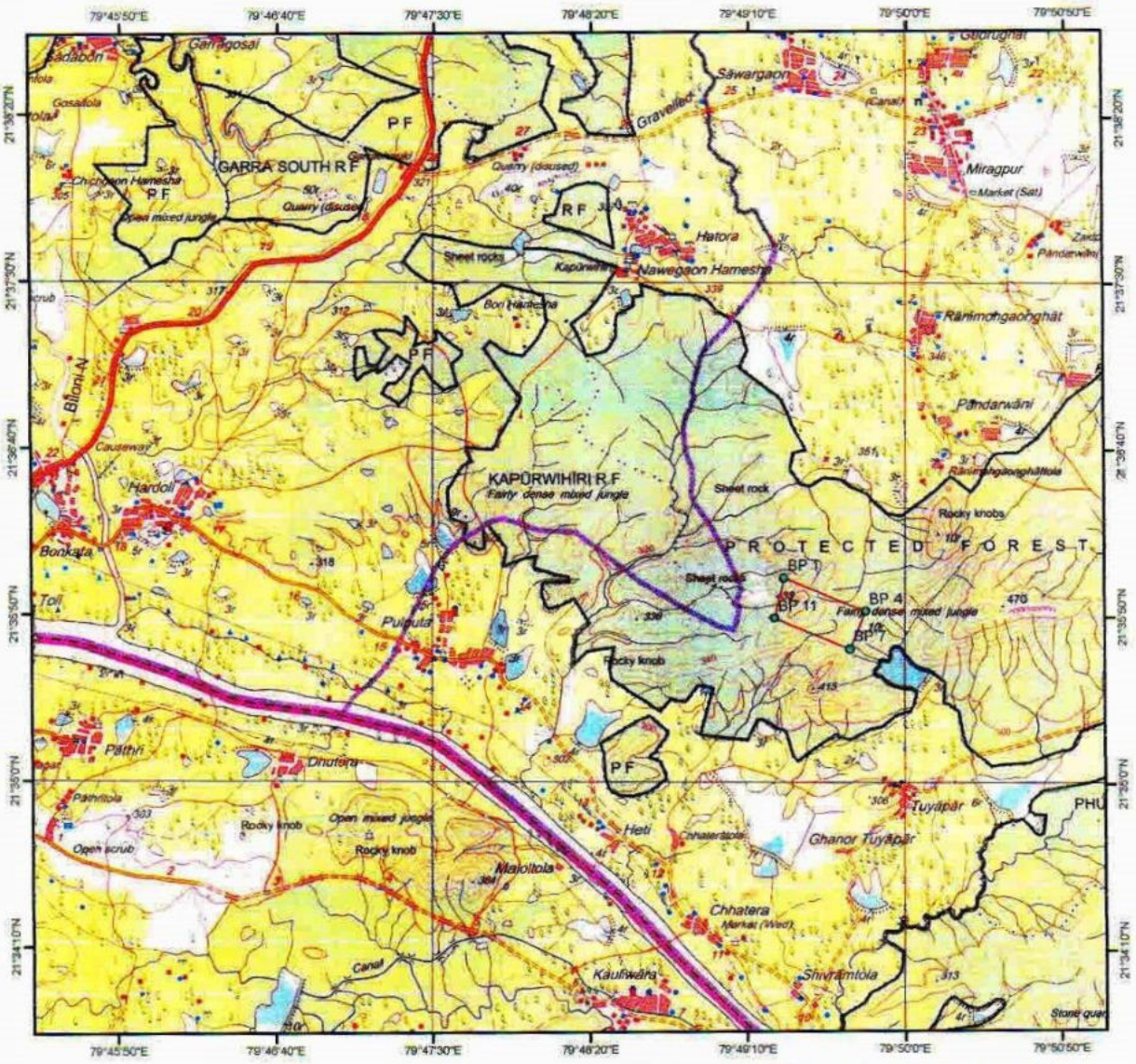

Legend

- Lease Area Boundary
- Study Area Boundary

Scale

0 0.5 1 2 KM

CLIMATE

The temperature of the area ranges from 8^0C to 43^0C. Minimum temperature is in January and maximum in May. The average annual rainfall is 1153.6 mm.

SOILS

The area has two types of soil. The mine area has no soil cover, but the area south of the mine area has soil which is suitable for paddy crop. As per the classification of Agricultural Survey of India, the soil in this area is deep, moderately well drained clayey soil with moderate erosion. It is associated with slightly deep well drained loamy soil.

Remaining area has deep, moderately well drained clayey soil on very gentle sloping and moderately dissected with moderate erosion. It is associated with slightly deep, well drained loamy soil.

LAND COVER/LAND USE

The area has Phulchur forest in the south, beyond the mine area. The study area has forest which is mixed jungle. In the west is Kapurwihiri forest which is mixed jungle. A small forest is in southern area near the river.

The area north and south of mine area is plain land which is used for agriculture.

SETTLEMENT MAP OF STUDY AREA

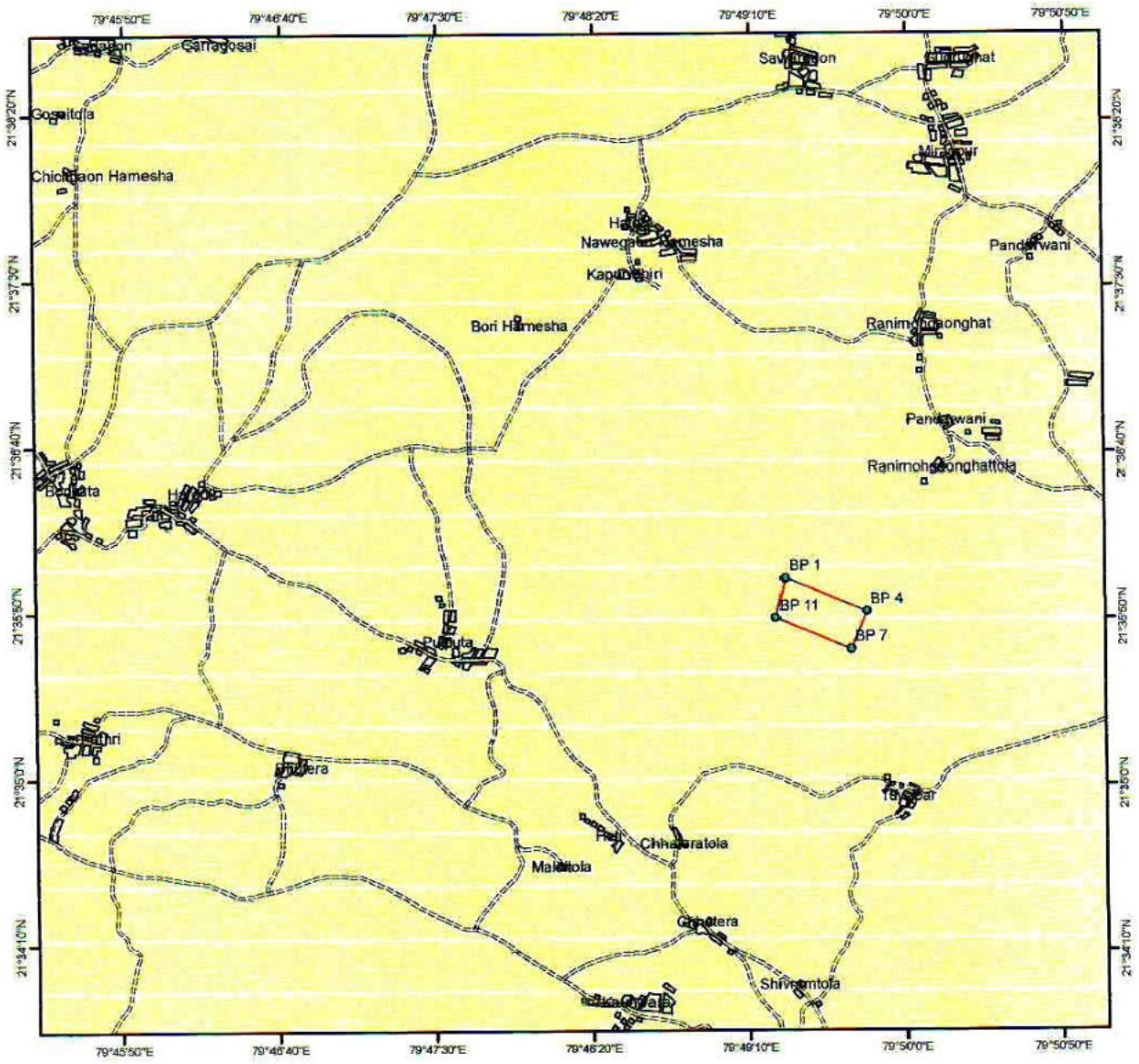

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Lease Area Boundary
- Roads
- Settlement
- Study Area Boundary

DRAINAGE

Being a hilly area the drainage is widespread and of different types. The drainage from the mine area is towards south. Initially, the drainage is almost parallel but the second order streams take a dendritic pattern. The entire drainage enters a big lake east of Tuyapar village. Further south, parallel drainage is again seen.

In the west, beyond the mine area, there is a network of drainage which is dendritic and directed towards south. This drainage feeds number of lakes and ultimately the river.

The dendritic drainage from the mine area towards southwest reaches a big lake near Ghanar village. As the drainage is coming from the entire ridge, the quantity of water will be more and that is why the lake is very big.

Looking at the drainage pattern in the area, there are fairly good chances of development of water resources. If properly planned and executed scientifically, the area can have perennial sources of water and sufficient groundwater storage.

GEOLOGY

The rocks of Balaghat area are of Pre-Cambrian and Archean age. The Bharweli- Ukwa groups of rock, extending upto Waraseoni and Tirodi, are the main manganiferous ore producing belt of central India.

After lot of study, field work and controversy, finally the stratigraphy of the area has been worked out. The area is divided into two major groups – the older is Sausar Group and the younger is Bharweli Group – separated by a Tectonic Contact.

PHYSIOGRAPHIC MAP OF STUDY AREA

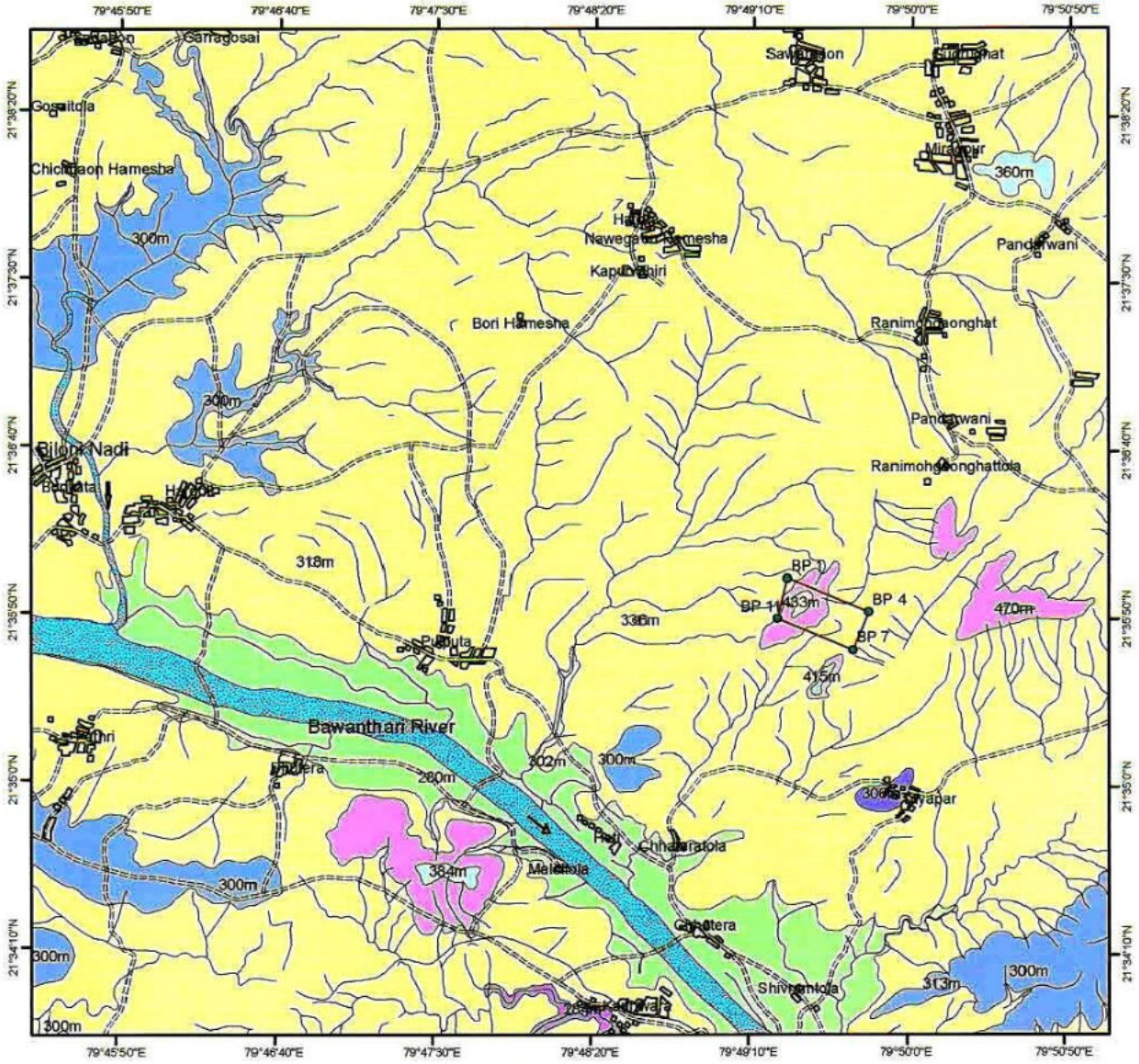

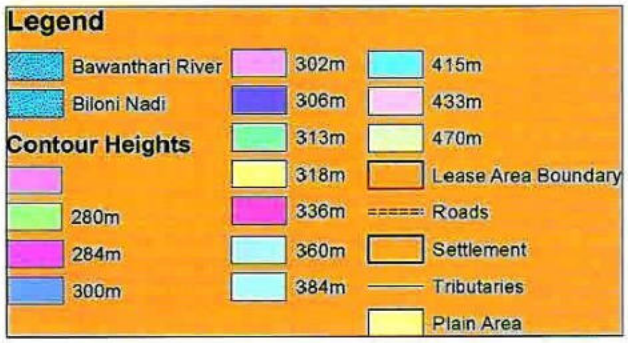

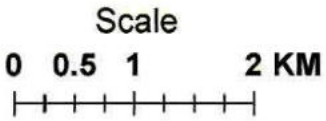

In the study area, the Biotite Schist/ Gneiss are the main rock types. At places, Granite Gneiss/Migmatite and Pegmatite Veins are encountered. The Biotite schist/ Gneiss have been hardened by the manganese solutions.

There had been intensive folding in this area which has rendered varying strikes and dip directions. The amount of dip ranges from 40^0-60^0. The general strike direction is northeast-southwest and the dip is towards northwest. As such, clear folding is not seen, but looking at the variation in dip directions and amount it is concluded that the rocks have been folded.

GEOMORPHOLOGY

There are deep and long escarpments in the northeast and southwest directions and the ridge slopes towards south, draining all the rain water towards the lakes and river. The heights contour value is 470 m above MSL and the lowest contour vale is 280 m above MSL.

The contour values suddenly fall in northwest and southeast directions. The northern most part of the area has a long pediplain, almost parallel to the escarpments. It has been developed by extensive erosion. In fact it is be product of coalescence of several pediments. There is a long chain of pediments in between the pediplain and escarpments.

The entire area around the mine is surrounded by forest. If the groundwater conditions are improved, the forest will also be benefitted.

GROUNDWATER OCCURRENCE AND MOVEMENT

The occurrence and movement of groundwater depends upon the availability of water, rock formation present in the area, topography, geology, structures, geomorphology and hydrological properties of the water bearing material. Massive rocks are aquifuse present in the study area. Fractures rock act as aquiclude and the weathered rocks and alluvial covered zone comes under

DRAINAGE AND SURFACE WATERBODIES MAP OF STUDY AREA

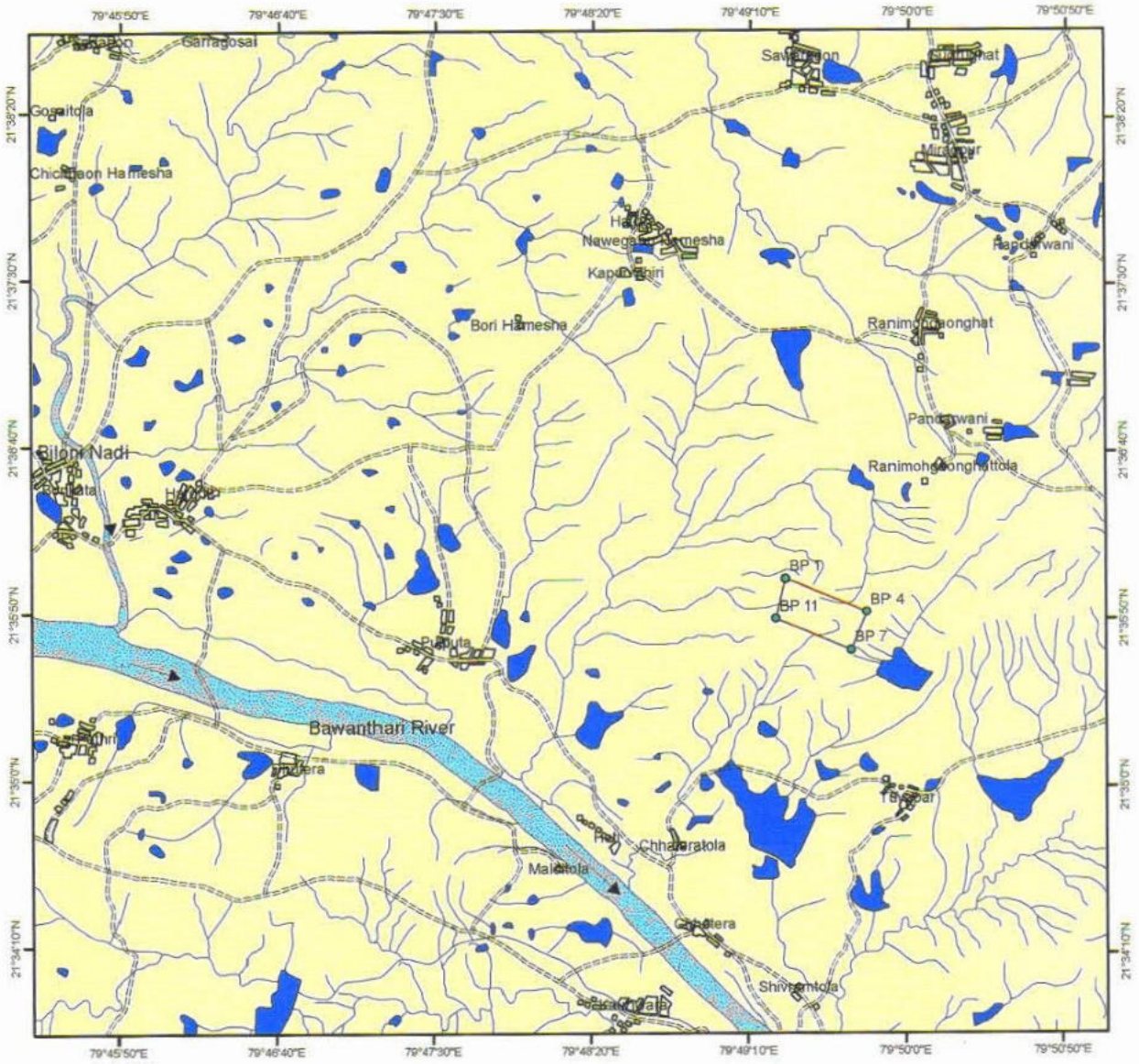

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Bawanthari River
- Biloni Nadi
- Lease Area Boundary
- Roads
- Settlement
- Surface Waterbodies
- Tributaries
- Study Area Boundary

GEOMORPHOLOGICAL MAP OF STUDY AREA

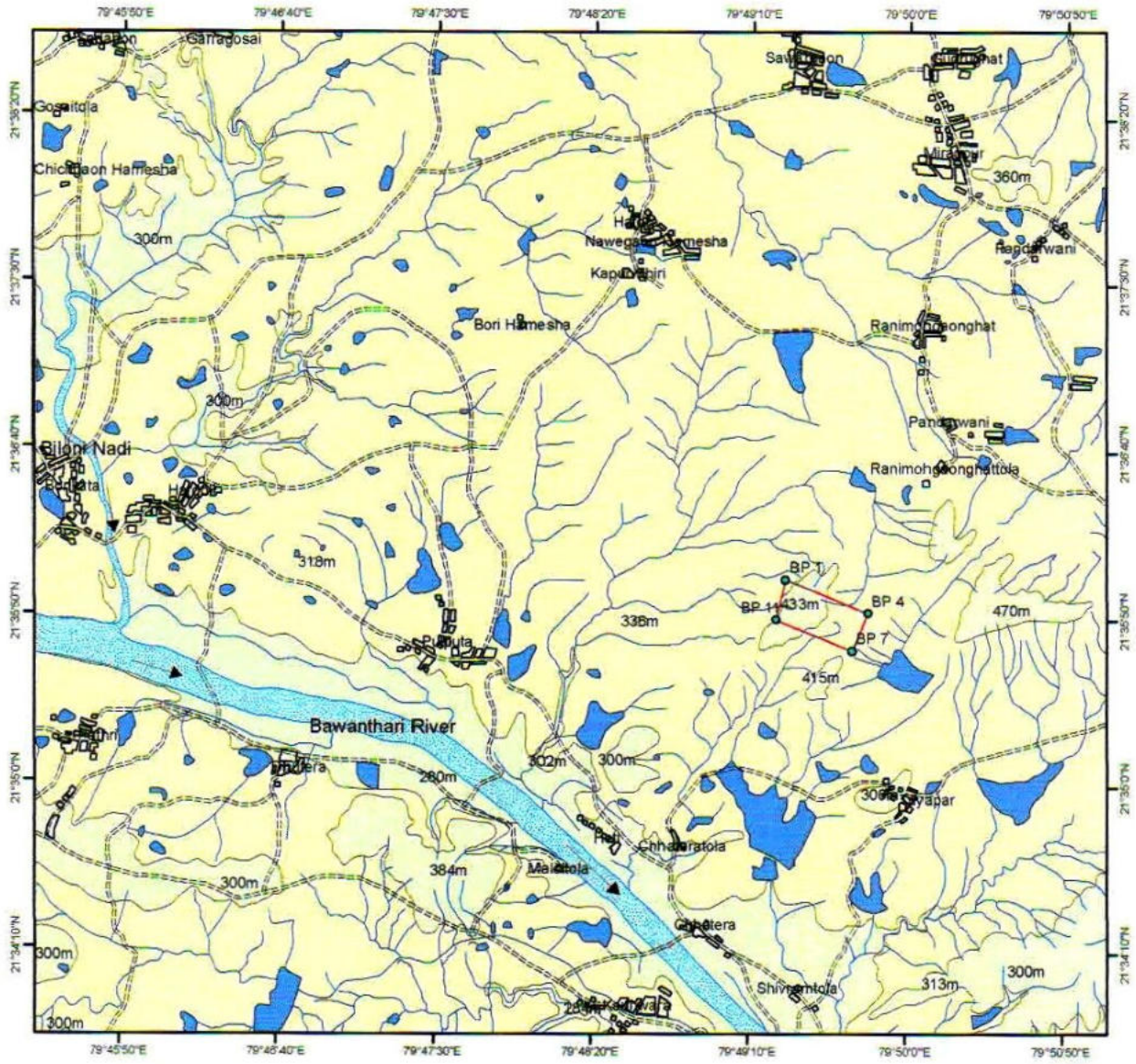

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Bawanthari River
- Biloni Nadi
- Denudation Hills
- Lease Area Boundary
- Roads
- Settlement
- Surface Waterbodies
- Tributaries
- Pediplain

act as aquiclude and the weathered rocks and alluvial covered zone comes under the water bearing formations as aquifer. These formations, on the basis of their hydrological properties can be classified as follows-

1. Unconsolidated alluvium/ soil zone

2. Weathered rock zone

3. Fractured and jointed rock zone

4. Massive rock zone

1. Unconsolidated alluvium/ soil zone- These zone occupies almost 50-55% of the area surrounding the mine area. It has variable thickness. It is a productive aquifer yielding good quality of groundwater. This zone is composed of boulder, cobble, pebble, sand, silt, clay etc. the sand rich alluvial/ soil zone is highly porous and contains huge amount of water. The presence of clayey bands and mixture of clayey loamy soil reduces its permeability. This zone is unconfined aquifer

2. Weathered rock zone – This zone contains partially weathered rocks which has been decomposed and disintegrated. This zone also contains good quality of water.

3. Fractured and jointed rock zone- This zone is not widely distributed. It contains less quantity of water along the secondary pore space. It is a confined aquifer.

4. Massive rock zone- It is exposed in the central part of the study area. Secondary porosity is developed in deeper zones but the more compact rocks do not have any opening. This zone has no water.

GROUNDWATER INVENTORY

For conducting groundwater survey in the study area 19 representative wells spread throughout the area have been taken into consideration for the inventory. The area is covered by forests from all sides and is very thinly populated. There are only number of villages and well. The pre-monsoon groundwater levels have been measured, recorded and analyzed.

WELL INVENTORY DATA

S. No.	Village name	Height of Parapet (m)	Depth of bedrock (m)	Actual depth of bedrock (m)	Depth of water level (m)	Actual depth of water level (m)	MSL (m)	Reduced level (m)	Coordinates
		A	B	B-A	C	C-A			
1	Mohagao Ghat 1	1.6	8.5	6.9	7.3	0.4	352	351	21^{0}37'9'' N 79^{0}50'4''E
2	Mohagao Ghat 2	1.1	11.1	10	9.1	8	365	357	21^{0}36'35'' N 79^{0}50'11''E
3	Mohagao Ghat 3	0.0	12	12	10	10	362	352	21^{0}36'58'' N 79^{0}50'6''E
4	Panderwani 1	0.0	7.2	7.2	7.5	7.5	356	348	21^{0}36'49'' N 79^{0}50'10''E
5	Panderwani 2	0.0	9.1	9.1	8.2	8.2	358	350	21^{0}36'44'' N 79^{0}50'21''E
6	Tuiyapar 1	1.1	12.2	11.1	9.3	8.2	302	294	21^{0}34'54'' N 79^{0}50'2''E
7	Tuiyapar 2	1.1	9.2	8.1	9	7.9	303	295	21^{0}34'47'' N 79^{0}49'50''E
8	Tuiyapar 3	0.8	7	6.2	5.8	5	286	281	21^{0}34'39'' N 80^{0}49'26''E
9	Chhatera 1	0.0	7	7	4.2	4.2	286	282	21^{0}34'43'' N 79^{0}48'57''E

10	Chhatera 2	0.4	16	15.6	14.1	13.7	287	273	$21^0$34'33'' N $79^0$48'48''E
11	Chhatera 3	0.0	8.2	8.2	7	7	287	280	$21^0$34'51'' N $79^0$48'45''E
12	Puliputta 1	0.0	26	26	14	14	285	271	$21^0$34'43'' N $79^0$48'25''E
13	Puliputta 2	0.5	10.4	9.9	9	8.5	285	276	$21^0$35'21'' N $79^0$48'4''E
14	Puliputta 3	0.5	6.7	6.2	3	2.5	287	284	$21^0$35'37'' N $79^0$47'30''E
15	Navegao 1	1	7	6	Dry	Dry	330	330	$21^0$37'16'' N $79^0$47'56''E
16	Navegao 1	0.0	9.4	9.4	9.1	9.1	345	336	$21^0$37'29'' N $79^0$48'36''E
17	Kapurbihri	0.4	5.3	4.9	5.1	4.7	343	338	$21^0$37'35'' N $79^0$48'33''E
18	Miragpur 1	0.9	9	8.1	5.8	4.9	355	350	$21^0$37'52'' N $79^0$50'18''E
19	Miragpur 2	1	11.3	10.3	8.4	7.4	368	361	$21^0$38'10'' N $79^0$50'18''E

GROUNDWATER FEATURES

The surface drainage is from north to south and the groundwater also flows in the same direction. Some groundwater contours are in the west and central part of the study area. The highest contour value is 361 m above MSL, which is in the central part and the lowest contour value is 271 m above MSL in deep south. There are two basins surrounding a mount in south, as is evident in the map. Another prominent basin is in west which is near the lineament and it can be a potential zone for groundwater development. A basin is also situated in the central part, south of Miragpur. The groundwater flowing from north to

WELL LOCATION MAP OF STUDY AREA

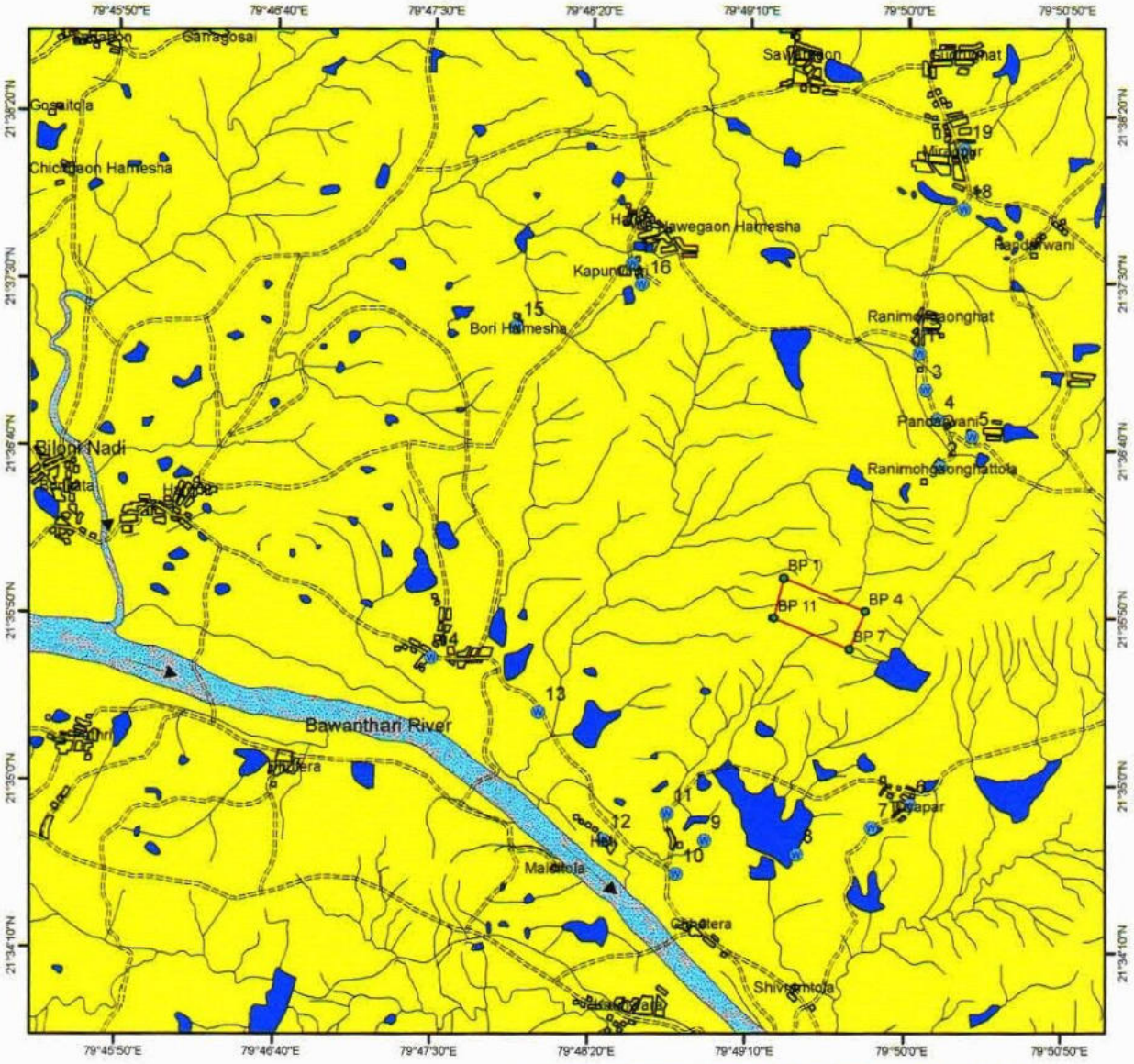

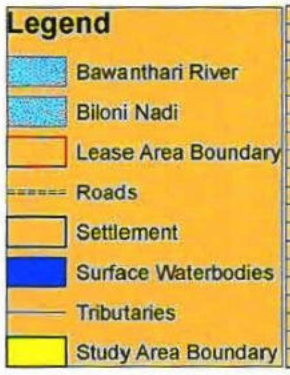

S.N.	LATITUDE	LONGITUDE
1	21°37'9.053"N	79°50'3.903"E
2	21°36'35.235"N	79°50'11.094"E
3	21°36'58.054"N	79°50'6.052"E
4	21°36'48.926"N	79°50'10.027"E
5	21°36'43.978"N	79°50'20.961"E
6	21°34'54.097"N	79°50'2.013"E
7	21°34'47.033"N	79°49'50.059"E
8	21°34'38.947"N	79°49'25.985"E
9	21°34'42.926"N	79°48'56.927"E
10	21°34'33.06"N	79°48'47.999"E
11	21°34'50.93"N	79°48'45.046"E
12	21°34'43.044"N	79°48'25.147"E
13	21°35'20.993"N	79°48'4.092"E
14	21°35'37.369"N	79°47'29.842"E
15	21°37'15.707"N	79°47'55.969"E
16	21°37'28.898"N	79°48'35.614"E
17	21°37'34.56"N	79°48'33.175"E
18	21°37'52.339"N	79°50'18.125"E
19	21°38'10.408"N	79°50'17.981"E

WELL LOCATION AND WATERTABLE CONTOUR MAP OF STUDY AREA

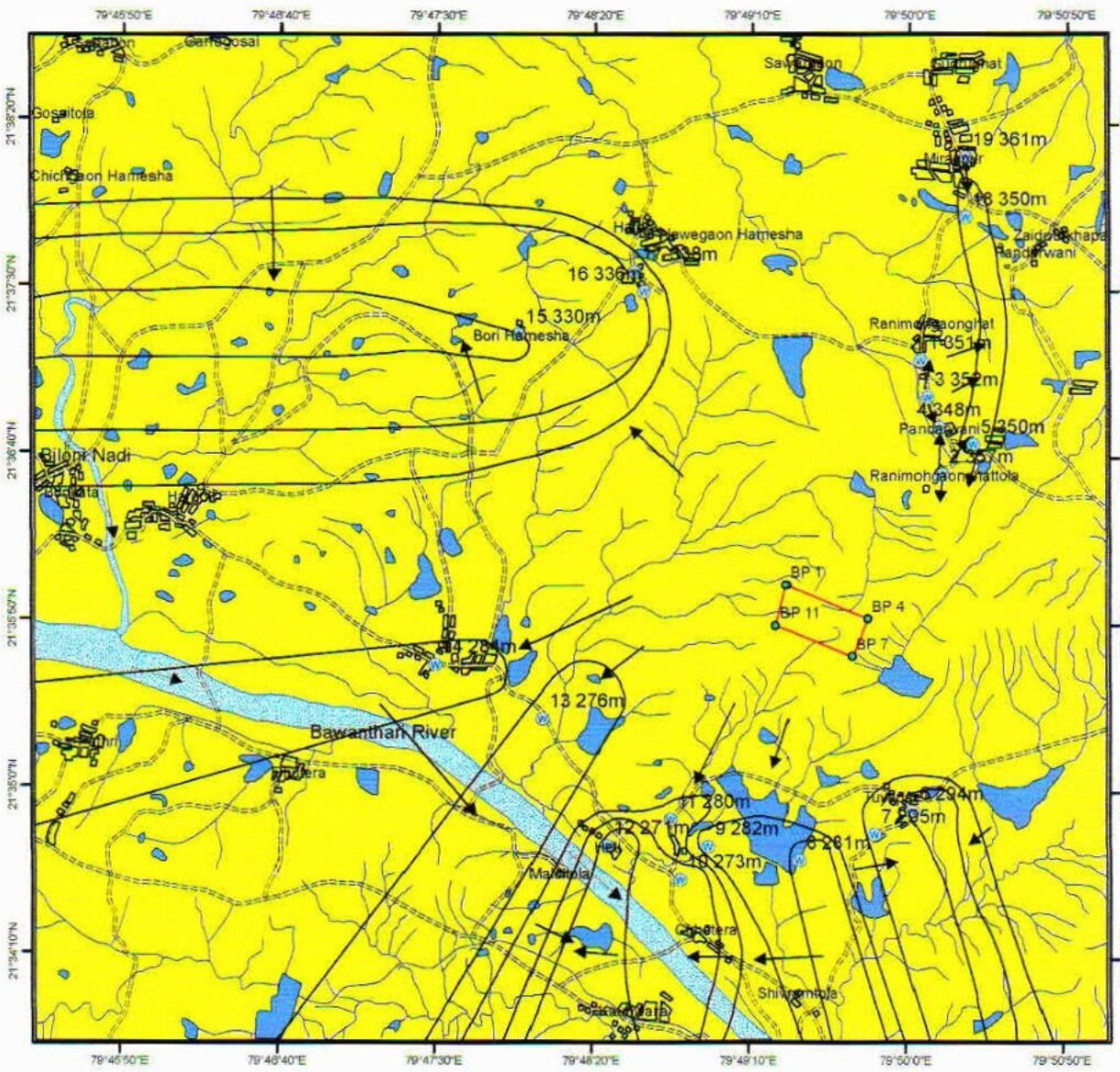

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Bawanthari River
- Biloni Nadi
- Lease Area Boundary
- Roads
- Settlement
- Surface Waterbodies
- Tributaries
- Watertable Contours
- Well location
- Study Area Boundary

HYDRAULIC GRADIENT MAP OF STUDY AREA

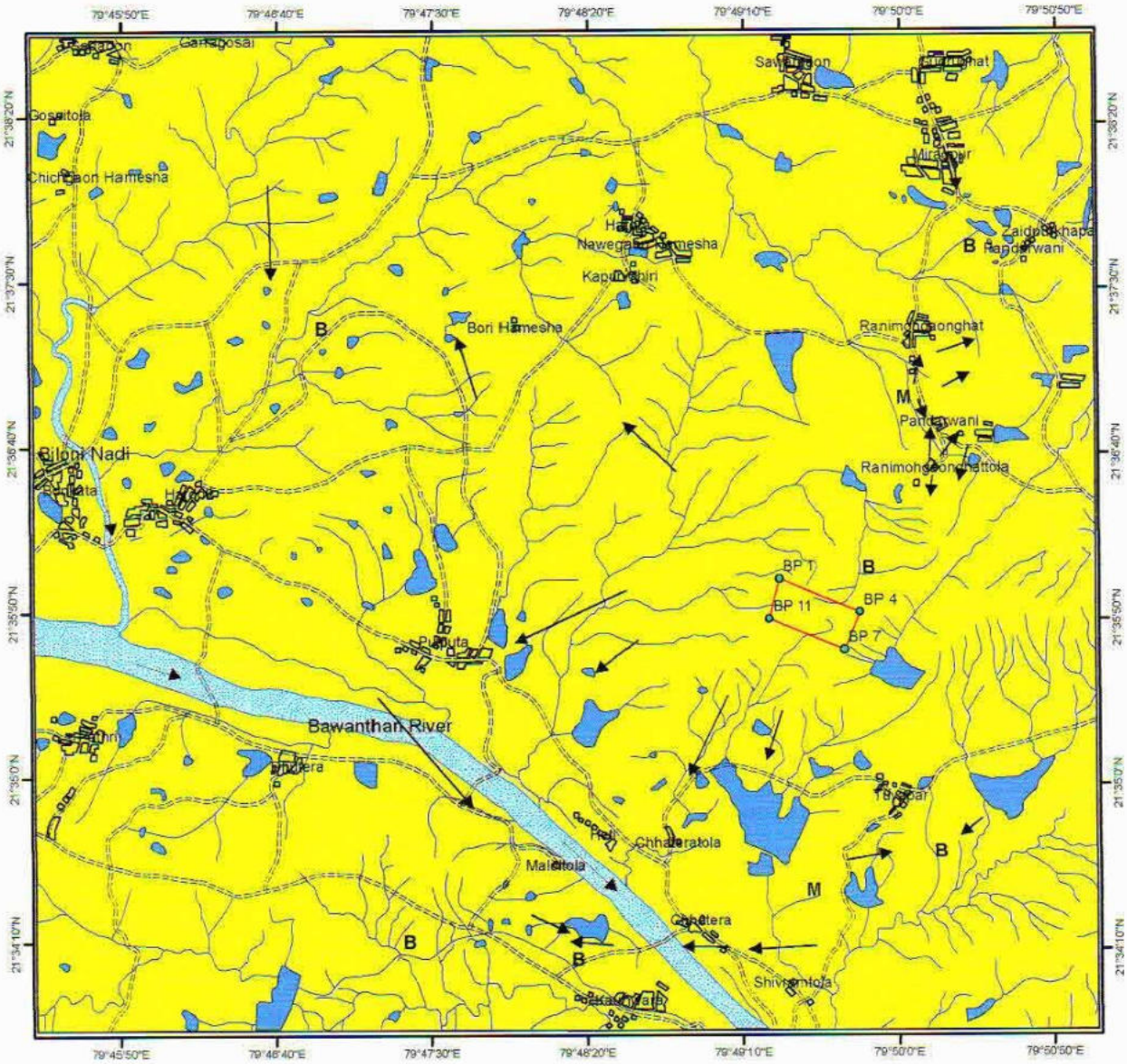

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Bawanthari River
- Biloni Nadi
- Hydraulic Gradient
- Lease Area Boundary
- Roads
- Settlement
- Surface Waterbodies
- Tributaries
- Study Area Boundary

the central part, south of Miragpur. The groundwater flowing from north to south crosses the mine area.

QUALITY OF WATER

Water is basic to all life forms- plants, animals and human beings. Water has a fairly constant composition, as is evident from the analysis report.

Water samples have been collected from different places in the early morning to avoid contamination by the users. The wells which are regularly used for domestic and irrigational purposes were selected for sampling. The collected samples were taken carefully to the laboratory of Groundwater Survey Department, Balaghat for analysis.

The results of the analysis are given in the table.

Drinking Water Standards established by different organization

Sr. no.	Constituents	Units	U.S. Environmental Projection Agencies		ECAFE &UNESCO 1963		ICMAR1975		WHO1971		S.I.	
			Primary std.	Secondary std.	Permissibale std.	Excessive limit	Permisibale std.	Excessive limit	Highest desirable	Maximum permissible	Highest desirable	Maximum permissible
1.	Physical											
	Tubidity	JTV	-				5	25	5	25	10	25
	Colour	Hazen	-	-	-	-	5	25	5	50	5	50
	Taste&Odour	-	-	-	-	-	Not dissgreeble	-	Unobjectionable	-		Unobjectionable
2.	Chemical		-									
	p^H				7.0-8.5	6.5-9.2	7.0-8.5	6.5-9.2	7.0-8.5	6.5-9.2	6.5-8.5	8.5-9.2
	T.D.S	Mg/l	-	500	500	1500	500	1500	500	1500	500	1500
	TH as $CaCo_3$	Mg/l					300	600	100	500	300	600
	Calcium	Mg/l	-	-	75	200	75	200	75	200	75	200
	Magnesium	Mg/l	-	-	50	150	50	150	-	150	30	100
	Iron	Mg/l	-	0.3	0.3	1	0.3	1.0	0.05	1.5	.03	1
	Copper	-	-	1	1	1.5	1	3	0.05	1.5	0.05	1.5
	Zinc	-	-	5	5	15	5	15	5	15	5	15
	Chloride	-	-	250	200	600	250	1000	200	600	250	1000

	Phenolic Substance	-	-	-	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	Fluoride	-	2.2	-	1.5	1	2	0.6-0.9	0.8-1.78	0.6-1.2	0.6-1.2	1.5
	Nitrates	-	10	-	50	100	20	50	50	-	45	No relexation
	Sulphate	-	-	250	200	400	250	400	200	400	150	-
3.	Toxic elemental											
	Arsenic	Mg/l	0.05	-	-	0.2	-	0.2	-	0.05	0.05	No relexation
	Mercury	-	0.002	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	No relexation
	Cadmium	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	No relexation
	Chromium	-	0.05	-	-	0.05	-	0.01	-	-	0.05	No relexation
	Cynide as CN	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.05	0.05	-
	Lead	-	0.05	-	-	0.1	-	0.01	-	0.1	0.1	-
	Selenium	-	0.01	-	-	0.05	-	0.05	-	0.01	0.01	-
4.	Radio Activity											
	Gross alfae mitter	Pci/l	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Gross beta emitter	Pci/l	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-

CHEMICAL ANALYSIS OF WATER SAMPLES

(Water source- Dug well and Reservoir)

S. No.	Location		Analysis									
			Temp.	pH	EC	TDS	TH	CaH	MgH	Ca++	Mg++	Cl^-
1	Mohagaon Ghat 1		33.6	7.22	245	157.8	120	77	49	29.7	10.6	68.9
2	Panderwani 2		32.8	7.11	214	136.4	110	55	54	21.4	12.6	58.66
3	Reservoir		33.8	7.4	330	210.4	72	66	12	25.2	10.95	44.21
4	Chhatera 2		33.5	7.64	490	314.6	84	55	30	21.5	8.77	30.20
5	Puliputta 1		33.2	7.65	640	410.16	90	62	38	25	9.64	50.84
6	Navegaon 1		33.8	7.80	281	182.33	110	60	45	26.8	12.67	30.20
7	Kapurbihri		34.1	7.75	320	450.24	90	45	46	18.4	12.33	30.82
8	Miragpur 2		34.4	7.62	610	390.7	72	45	33	17.7	8.77	30.20

DISCUSSION

The analysis was done considering ten parameters. On comparison of the analysis with Indian Standard of Drinking Water it is observed that pH, TH, CaH, MgH, Ca, Mg and CL are within highest desirable range. However, EC and TDS are slightly high in village Pandarwani 2 and Reservoir, but within permissible limit. Suitable methods for purification of drinking water should be adopted by the villagers.

LINEAMENTS

A lineament is a map-able, simple or composite linear feature of a surface, whose parts are aligned in a rectilinear or slightly curvilinear

LINEAMENTS MAP OF STUDY AREA

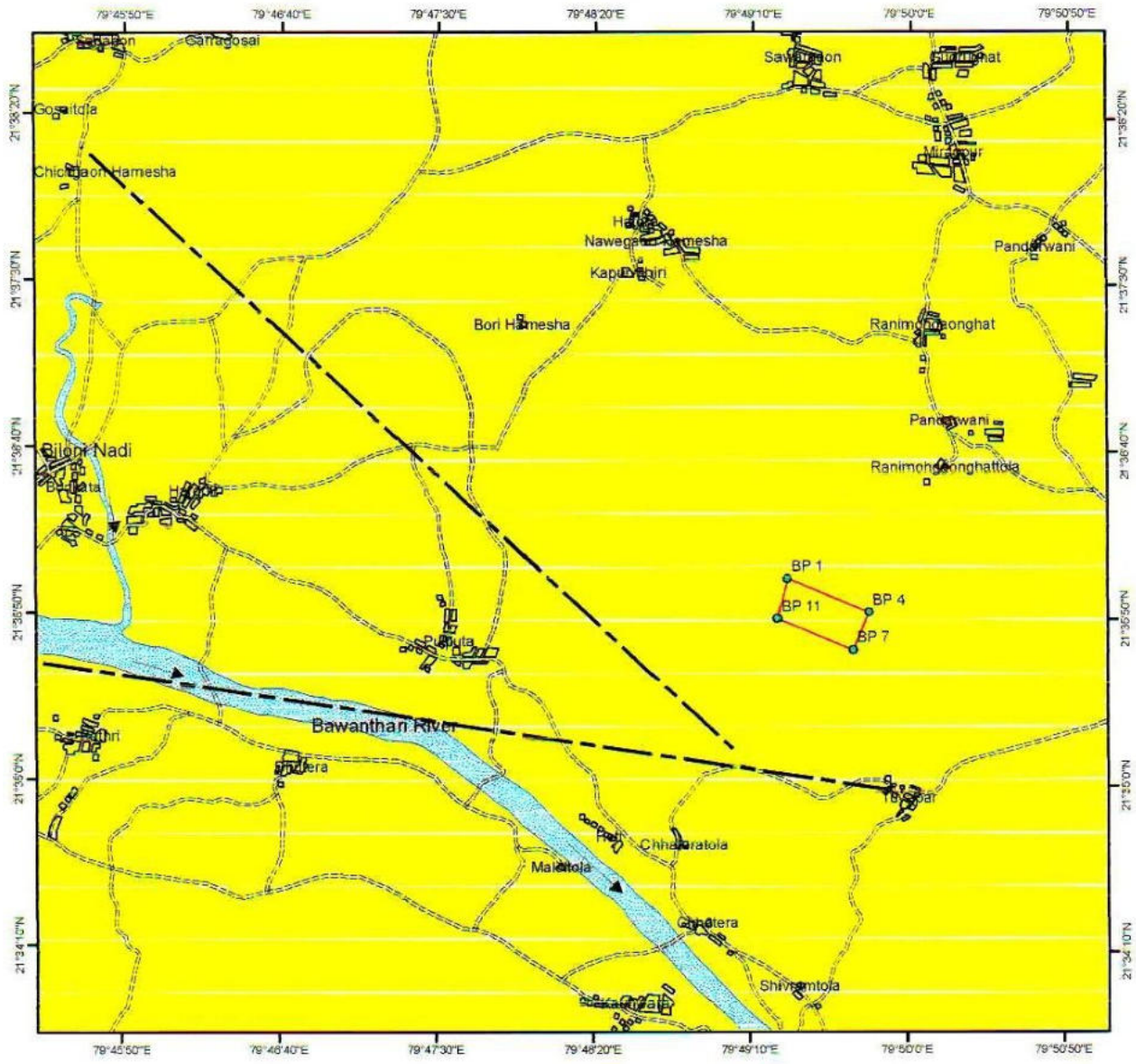

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Bawanthari River
- Biloni Nadi
- Lease Area Boundary
- Lineaments
- Roads
- Settlement
- Study Area Boundary

relationship and which differ distinctly from the pattern of the adjacent features and presumably reflects a subsurface phenomenon. Lineament may be a joint, fracture, fault etc. that has gone deep into the earth and is the best indicator of groundwater recharge and potential zone, expressed in the aerial photograph or landsat imagery.

In the study area, two prominent lineaments have been identified. One lineament is from the northwestern corner of the study area and extends towards southeast. This lineament crosses Garra South and Kaapurihiri Reserve Forest and is almost at the fag end of the mining lease area. The second lineament is from southwest and extends up to southeast. It crosses the river and ends near Tuyapar village. Looking at the hydraulic gradients, almost entire groundwater movement is towards south and southwest. It crosses the lineament at several places.

GIS STUDIES

Geomorphic Information System (GIS) is a set of computer tools that allows working with data that are tied to a particular location. It is a database that is specially designed to work with map data. GIS works with many different applications- land use planning, environmental and groundwater management etc.

Different pairs of thematic maps were superimposed for GIS studies. They are as follows-

1. Interrelation of geomorphology and water table contours

The central part of the study area is a hilly tract and there are no villages in this area. Maximum water table contours are towards south. Some contours are in west and central part. There is complete harmony between the geomorphology and water table contours.

2. **Interrelation of lineaments, surface water bodies and drainage**

Maximum drainage of groundwater is from north to south. The major lineament extending from west to east crosses the river and some tanks. It also crosses number of streams. There are maximum villages in this area.

3. **Interrelation of lineaments, hydraulic gradients and water table contours.**

Maximum hydraulic gradients are dipping towards the major lineament in the west-east direction. Some of the hydraulic gradients are almost parallel to the lineament which is in northwest-southeast direction. Some of the contours in the south cut across the lineament from west to east and similar conditions are around the other lineament. Three prominent groundwater basins are very near to the west-east lineament and one basin crosses the northwest-south-east lineament. This is a favorable condition.

GROUNDWATER POTENTIALS

The mine area and its surrounding are hilly and covered with forest. The soil cover on the hills is scanty and maximum water flows down. The soil cover in the remaining area has alluvium and clay which has good porosity and permeability and paddy field are in this area. The fractured and jointed zone in the hills has poor permeability but where secondary porosity is developed by the tectonic activity and infiltration of water is possible. The groundwater potential of these rocks depends upon their fracture-joint system and their intensity.

The weathering depends upon the environmental factors like climate, topography, vegetation and slope conditions, apart from rock types. The degree

SUPERIMPOSED MAP OF GEOMORPHOLOGY AND WATERTABLE CONTOURS MAP OF STUDY AREA

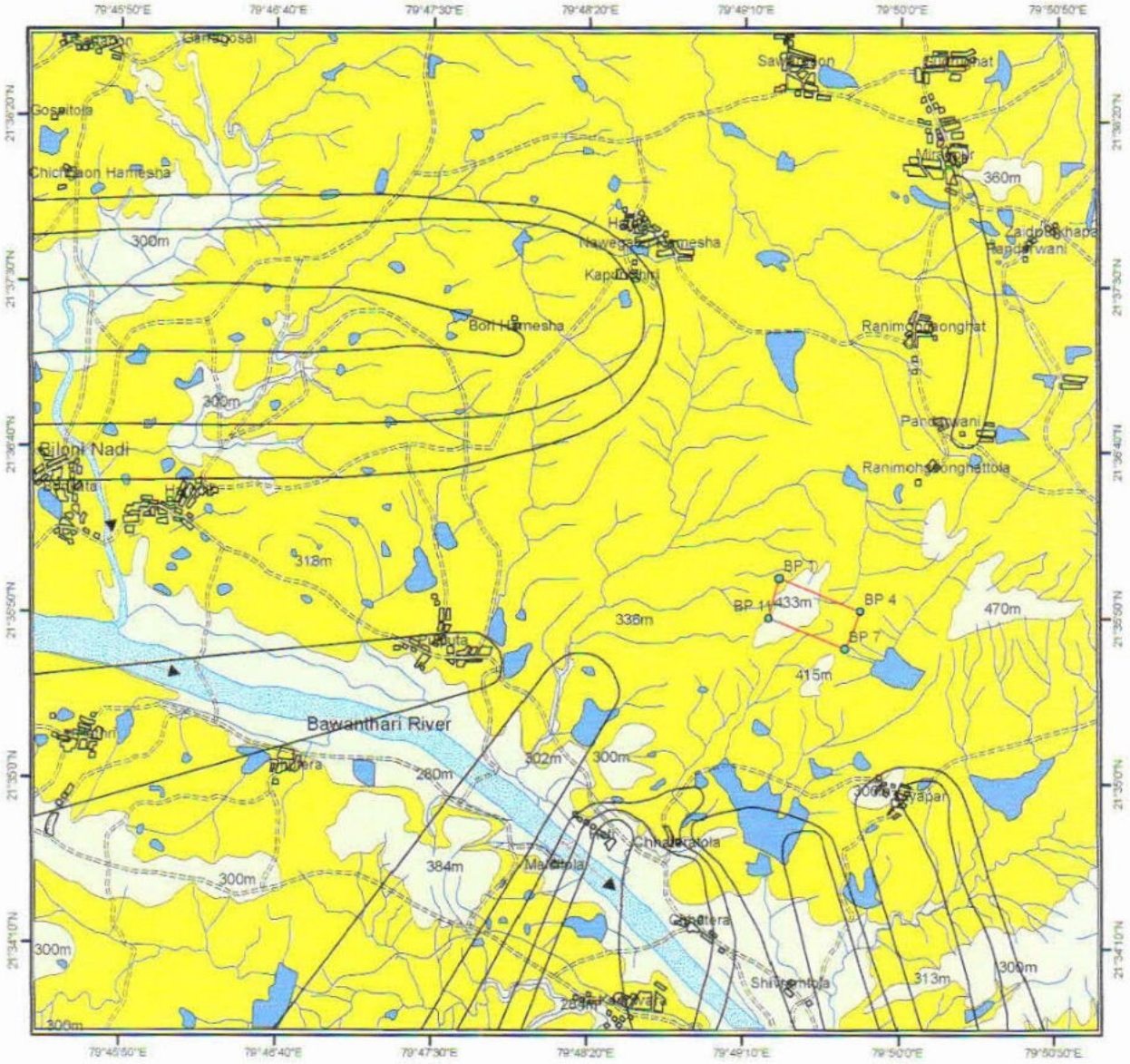

SUPERIMPOSED MAP OF LINEAMENTS AND DRAINAGE AND SURFACE WATERBODIES MAP OF STUDY AREA

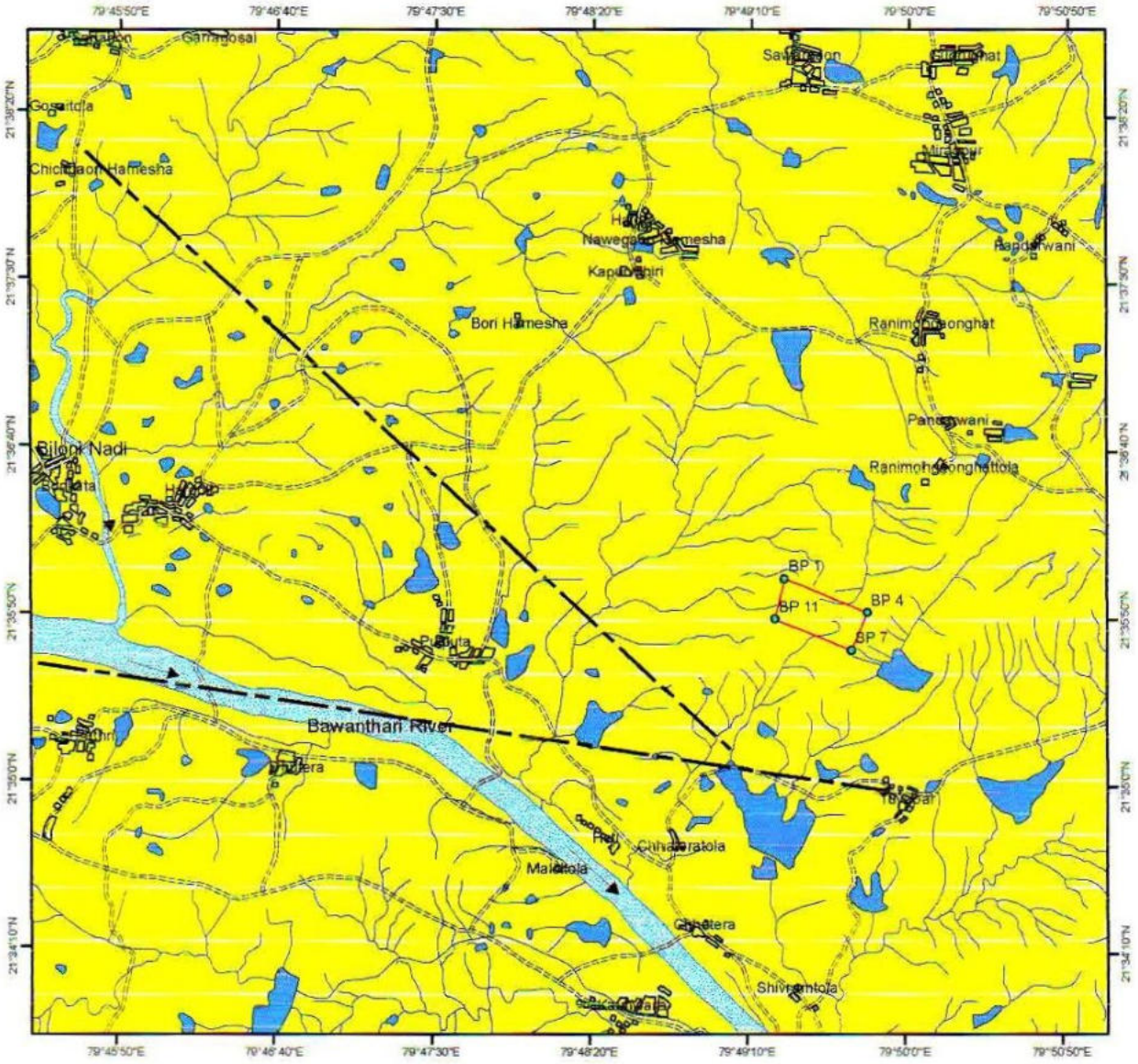

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Bawanthari River
- Biloni Nadi
- Lease Area Boundary
- Lineaments
- Roads
- Settlement
- Surface Waterbodies
- Tributaries
- Study Area Boundary

SUPERIMPOSED MAP OF LINEAMENTS AND WATERTABLE CONTOURS AND HYDRAULIC GRADIENT MAP OF STUDY AREA

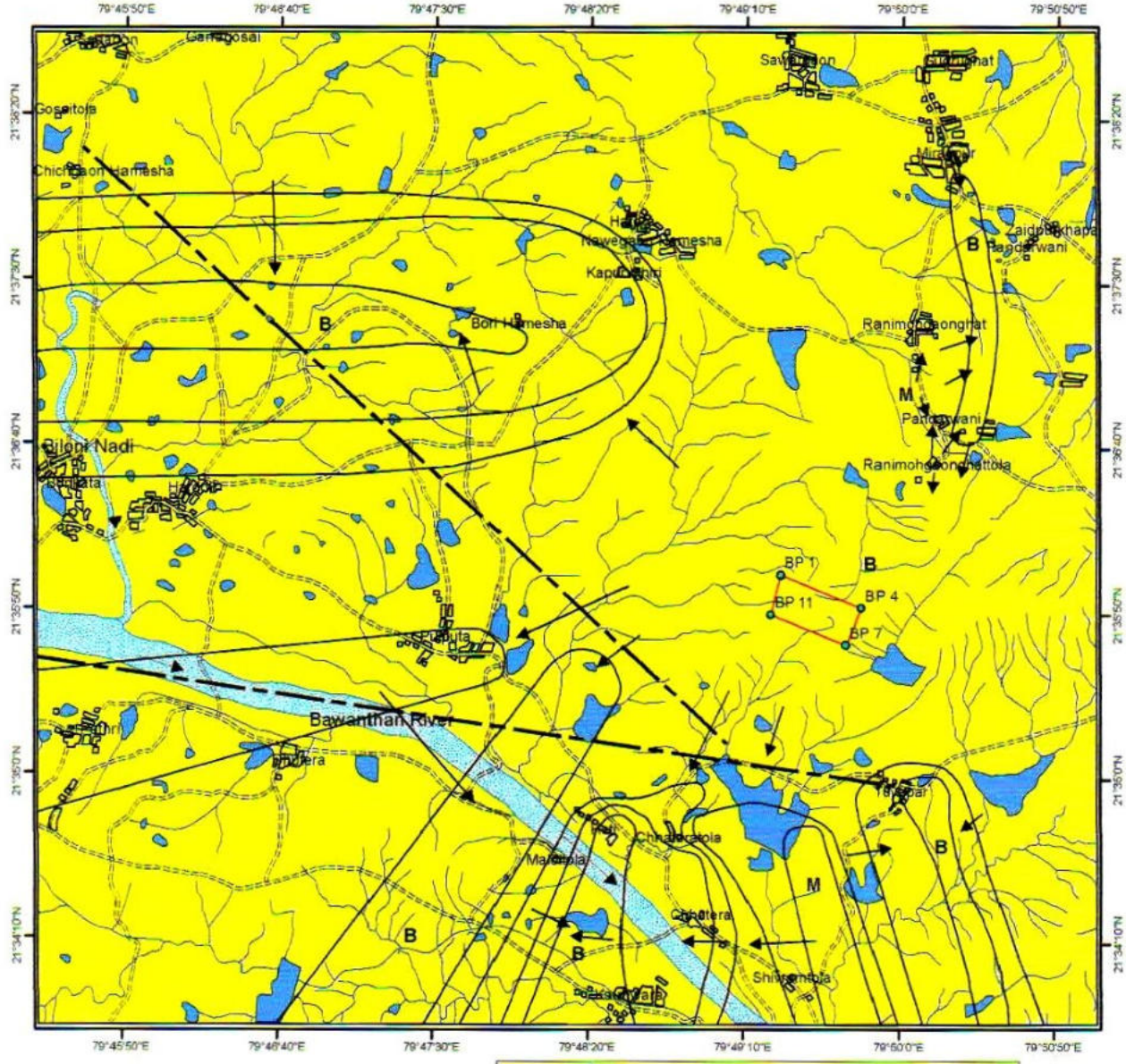

Scale

0 0.5 1 2 KM

Legend

- Bawanthari River
- Biloni Nadi
- Hydraulic Gradient
- Lease Area Boundary
- Lineaments
- Roads
- Settlement
- Surface Waterbodies
- Tributaries
- Watertable Contours
- Study Area Boundary

of weathering is another factor influencing the permeability of the disintegrated rocks. In completely weathered rocks, the primary minerals are usually replaced by clay minerals and hence the residue would be almost clayey, as seen in the central and southern part of the study area.

The groundwater potential of an area depends on the rainfall and particularly, on run in. The run in depends on the rate of infiltration and recharging areas, drainage density, topography, lithology, vegetation etc.

Considering all the factors, it is concluded that this area is of medium rainfall and most of the rainwater runs off from north to south and very little part of it infiltrates. The soil cover in the remaining area, which covers almost 50-55% of the entire area, receives the water from the hilly tract and it is infiltrated. Drainage density is high, which is a favorable factor.

For a complete assessment of the groundwater conditions it is imperative to evaluate the annual groundwater recharge and annual groundwater draft. Then only water budget can be drafted. For annual groundwater draft, complete demographic data is required.

CONSERVATION PLAN OF SURROUNDING WATER RESERVOIR

The reservoir adjoining the mine lease area has to be developed for conservation of water. Salient features of the reservoir are-

Total area of the Reservoir- 9.436 Hectare

Co-ordinates

1. Latitude $21^0$35'41.842"N- Longitude $79^0$49'57.66"E
2. Latitude $21^0$35'33.104"N- Longitude $79^0$49'51.392"E

WATER TANK NEAR LEASE AREA BOUNDARY

Scale

0 0.5 1 2 KM

S.N.	LATITUDE	LONGITUDE
1	21°35'41.842"N	79°49'57.66"E
2	21°35'33.104"N	79°49'51.392"E
3	21°35'27.3"N	79°50'3.142"E
4	21°35'32.267"N	79°50'7.629"E

Water Tank Area 9.436 Hec.

Legend

- Water Tank Boundary
- Lease Area Boundary
- Study Area Boundary

3. Latitude $21^0$35'27.3"N- Longitude $79^0$50'3.142"E
4. Latitude $21^0$35'32.267"N- Longitude $79^0$50'7.629"E

EXCAVATION OF PART OF PERIPHERY OF THE RESERVOIR

Periphery- 1.5 Km. (including length of the earthen dam which is 20 m long). A part of the periphery can be excavated to increase the size of the reservoir and its water holding capacity.

The Formula for excavation work is

$$k= PD/S$$

Where,

k= constant

P= Number of labors

D= Number of days

S= Cubic meter (cum) of soil excavated

Supposing 25 labors work for 6 day and excavate 500 cum of soil, then-

$$k=PD/S$$

$$= (25x6)/500$$

$$= 3/10 \text{ cum per day/labor}$$

The part of the periphery of the reservoir which is towards BP 7 from where the drainage is coming is about 100 m in length.

If this part of the periphery is excavated up to 2m depth and 2m width the volume of soil to be excavated will be 100x2x2 = 400 cum.

As per the above formula a labor can excavate 3/10 cum/day. If 50 labors are employed for the work, they will excavate the entire periphery of 400 cum @ 15cum/day in 26.66 days.

The Govt. rates the payment of unskilled labor is Rs. 258=00 /day

Therefore the payment for 50 labors working for 27 days will be-

50x27x258= Rs. 3,48,000=00

DESILTING OF THE BASE OF EARTHEN DAM

The earthen dam is 20 m long. Maximum silting is at the base of the dam, which has to be removed. The labor rates and working is the same as in the case of excavation.

Therefore, for desilting 20 m length, 1.5 m width and 2 m depth, as per the above formula a labor can excavate 3/10 cum/day. If 10 labors are employed for the work, they will desilt 60 cum @ 3cum/day in 20 days.

The Govt. rates the payment of unskilled labor is Rs. 258=00 /day Therefore the payment for 10 labors working for 20 days will be-

10x20x258= Rs. 51,600=00

REPAIR AND MAINTENANCE OF EARTHEN DAM

This work can only be done after inspection of the dam by an expert engineer. Tentatively, a budget of Rs. 1,00,000=00 can be allotted for this work.

GRAND TOTAL OF EXPENDITURE ON CONSERVATION PLAN OF SURROUNDING WATER RESERVOIR

3,48,000 + 51,000 + 1,00,000

= Rs. 4,99,600=00

(Rupees four lakhs ninety thousand and six hundred only)

CONCLUSION

In general, the groundwater conditions in hard rock terrain of Archean and Pre-Cambrian age are poor. It depends on the permeability of soil, weathered, fractured and jointed zones. Geomorphology and drainage also play an important role. In the study area, the hilly tract in centre and southern part

drains the rainwater towards south which has resulted in form of number of lakes. The drainage is scattered and drainage density is high.

The water table contours and hydraulic gradients depict that there are groundwater basins in the south near village Tuyapar, Hoti and Maloltola. In between, there is a mount near village Shivramtola. In the west there is a big groundwater basin near village Bori and Hamesha. Another groundwater basin is south of village Miragpur. A basin is also near the mining lease area but some part of the groundwater runs in the south direction, as is evident from the hydraulic gradients. The soil cover on the hilly tract is very thin and maximum water runs down the slopes. Therefore, construction of contour trenches will be futile. By opencast mining the water will be collected in pits which will be directed towards the Reservoir. There will be no ill-effect on agriculture by irrigating this water, as it has no pollutants.

There are no notified and endangered species of plants in this area, which may be affected due to mining activity. Therefore, biological environment will not have any significant impact due to proposed mining activity. The impact on biological environment because of the dust generated will be minimized by well developed green belt in and around the mining lease area. It will also compensate for the deforestation done during the development of the mine.

(Dr. Santosh Saksena)

Secretary
Geological Association & Research Centre
D.A. Museum,opp.Circuit House
BALAGHAT (M.P.) 481001